मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का सफल परीक्षण

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

RNI Regn. No.7789/1964 वर्ष-61 > अंक - 236 रायपुर गुरूवार 21 अगस्त 2025 विक्रम संवत 2082 पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 नए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमान

नईदिल्ली। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 97 एलसीए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि एक उच्चस्तरीय बैठक में विमानों की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। 62,000 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इन विमानों का उत्पादन करेगा।

नए ऑर्डर के बाद वायुसेना में तेजस विमानों की कुल संख्या 180 हो जाएगी। इससे पहले वायुसेना ने 83 तेजस विमानों का ऑर्डर करीब 48,000 करोड़ रुपये में दिया था। ये नए विमान मिग-21 विमानों की जगह लेंगे। बता दें कि मिग-21 विमान पुराने हो चुके हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। इसी वजह से इन्हें चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से बाहर किया जा रहा है।

लोकसभा में गृहमंत्री शाह ने पेश किए तीन बिल , विपक्ष का जबरदस्त हंगामा

जेल से सरकार चलाना जनमत का अपमान

अब गंभीर आरोपों पर छोड़नी होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कुर्सी

नईदिल्ली,संवाददाता।

संसद के मानसून सत्र का बुधवार को 20वां दिन है. मानसून सत्र के समाप्त होने में अब सिर्फदो दिन बचे हैं. ऐसे में सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन अहम विधेयकों को पेश किया, उनमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री के गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर पद से हटाने वाला विधेयक भी शामिल है. इस विधेयक के खिलाफसंसद में जोरदार हंगामा हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए कहा कि जेल से सरकार चलाना जनता के जनमत का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बुधवार को शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए. इन विधेयकों में प्रावधान है कि चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अगर उस पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहे तो उन्हें अपने पद से हटना होगा.

विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार अगर कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में लगातार

30 दिन जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। इस मामले में अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो मंत्री 31वें दिन के बाद स्वतः ही पद से हट जाएंगे। कोई राज्य मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहा, तो राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह से हटाएंगे।

अगर राज्य के मंत्री को हटाने की सलाह मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो 31वें दिन मंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहे तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका भी पद समाप्त होगा। इसी तरह, प्रधानमंत्री अगर खुद ऐसे गंभीर आरोपों में 30 दिनों तक जेल में रहें, तो उन्हें भी 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद खुद से समाप्त हो जाएगा। विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य मंत्री सहित कोई भी मंत्री को गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास) में गिरफ्तार या 30 दिनों की निरंतर अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है, उसे पद से हटाया जा सकेगा। प्रस्तावित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रयास करता है और इसमें नया खंड (4ए) जोड़ता है।

लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल ध्वनिमत से पास, 3 साल की जेल या 1 करोड़ की सजा होगी

ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेग्यूलेशन बिल बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया. इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है. इस बिल के कानून बनने के बाद दोषी लोगों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है. मसौदा कानून पारित होने के तुरंत बाद विपक्ष द्वारा की गई मांगों को लेकर किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

बिल में ये हैं प्रावधान - इस बिल में ऑनलाइन गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का भी प्रावधान है. ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियां गैरकानूनी घोषित यह विधेयक सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों ऑनलाइन फैंटी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी और अन्य गेम) को गैरकानूनी घोषित करता है।

पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन

एजेंसी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।

राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद थे।

4 सेटों में दाखिल हुआ नामांकन नामांकन चार सेटों में दाखिल हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर हैं, जबकि बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जो गठबंधन में व्यापक सहमति को दर्शाता है।

160 सदस्य रहे मौजूद

संसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित एनडीए के लगभग 160 सदस्य उपस्थित रहे। सीपी राधाकृष्णन को नामित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर आयोजित एनडीए के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

दिल्ली के 50 से अधिक स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत फैली

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 48 घंटे बाद फिर से 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर स्थित एसकेवी हौज रानी और करोल बाग स्थित आंध्रा स्कूल समेत 50 स्कूलों को बुधवार सुबह अज्ञात ईमेल मिले हैं। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंच गई। परिसर खाली करा लिया गया है। धमकी की सूचना के बाद पुलिस ने स्कूल परिसर को खाली करा दिया, जबकि कुछ बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। अभी कुछ स्कूलों की तलाशी चल रही है, जबकि कुछ स्कूलों में संदिग्ध सामान नहीं मिला है। इससे पहले भी सोमवार को सुबह 7-30 बजे से दोपहर 12-25 बजे के बीच 32 स्कूलों ने पुलिस को फोन करके ईमेल पर धमकी मिलने की जानकारी दी थी। सोमवार को पूरे दिन तलाशी में कुछ नहीं मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी से अब तक दिल्ली-एनसीआर के 74 शैक्षणिक संस्थानों, 70 स्कूलों और 4 कॉलेजों को बम से उड़ाने धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस धमकियां देने वालों को पकड़ने में असमर्थ है, क्योंकि वे ईमेल को गूगल से न भेजकर वीपीएन, डार्क वेबसाइट्स या अन्य तरीके से भेज रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह: विधायक गजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल गुरू खुशवंत साहेब बने मंत्री

लोकशक्ति।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हो गए हैं। तीनों नए मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेका ने आज यहां राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में गजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल, एवं गुरू खुशवंत साहेब को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्रीपरिषद के सदस्यगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया. इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना भी उपस्थित थे.

गजेंद्र यादव

स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य

खुशवंत साहेब

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास

राजेश अग्रवाल

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

मुख्यमंत्री ने कही ये बात - मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा- सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगीगण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं। सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। मंगलकामनाएं।

भारी बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, सड़क से आसमान तक यातायात प्रभावित

एजेंसी। मुंबई

मुंबई में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके चलते ट्रेन के पहिये थम गए हैं, जबकि विमानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा तेलंगाना, बिहार में ऑरेंज अलर्ट और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों में हल्की/मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में करीब 300एमएम बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं।

दिल्ली की रेखा गुप्ता पर हमला, हाथ पकड़कर खींचने की हुई कोशिश

सर पर मेज से लगी चोट

एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है. यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान की है. आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक, जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी. उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा. इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया. आरोपी को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया. शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है. आरोपी राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र 41 साल है. गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जानकारी दी है.

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने भी बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा. उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया. हालांकि, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सीएम को थप्पड़ मारे जाने से इनकार किया है।

हमले के बाद मैं सदमे में थी : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं. मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों. मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी. ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते. अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी।

विदेश टैरिफटेंशन के बीच रुस ने किया बड़ा ऐलान,

रूस अब भारत को 5% डिस्काउंट पर मिलेगा कच्चा तेल

एजेंसी

भारत और अमेरिका के टैरिफ टेंशन के बीच रूस ने साफकर दिया है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रुकने वाली नहीं है. अमेरिका की सख्ती और बढ़ते टैरिफ के बावजूद मॉस्को ने भरोसा दिलाया है कि भारत को आगे भी डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल मिलता रहेगा.

कच्चे तेल पर 5% का डिस्काउंट

रूस के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, एवगेनी ग्रिवा ने कहा कि आने वाले समय में भी सप्लाई स्थिर रहेगी और भारत को औसतन 5% तक की छूट मिलती रहेगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डिस्काउंट का सही स्तर कमर्शियल सीक्रेट है और इसमें ÷प्लस-माइनस 5%÷ का अंतर हो सकता है.

पुरानी दोस्ती पर है पूरा भरोसा

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ओर से कच्चे तेल का इंपोर्ट लगभग उसी स्तर पर बना रहेगा. वहीं, रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भले ही भारत पर बाहरी दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन मॉस्को को अपनी पुरानी दोस्ती पर पूरा भरोसा है. उनके अनुसार, ÷यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारत-रूस की ऊर्जा साझेदारी जारी रहेगी.÷

अमेरिका लगातार बना रहा है प्रेशर

इधर, अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बढ़ा रहा है. वॉशिंगटन का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीनरी को फंड कर रहा है. इसी कारण पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया, जो बचा हुआ 25% 27 अगस्त से लागू हो जाएगा. व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम रूस को यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से रोकने के लिए उठाए गए हैं. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति युद्ध को खत्म करने के लिए कड़ा पब्लिक प्रेशर बना रहे हैं और भारत पर लगे नए प्रतिबंध उसी रणनीति का हिस्सा हैं।

बिहार : औंटा-सिमरिया छह लेन पुल तैयार, 22 अगस्त को पीएम करेंगे उद्घाटन

- बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बनी नई 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री

पटना, संवाददाता ।

उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गंगा नदी पर एक और पुल बनकर तैयार है। मोकामा के औंटा घाट को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ने वाले सिक्स लेन पुल का उद्घाटन आगामी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। औंटा घाट से सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बने इस सिक्स लेन पुल की कुल लम्बाई 8.150 किमी है। जबकि गंगा नदी पर इस पुल की लम्बाई 1.865 किमी है। इस परियोजना की कुल लागत 1871 करोड़ रूपये है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बनी नई 4 लेन सड़क का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त को किया जाएगा।

राजेंद्र पुल के समानांतर तैयार हुआ यह नया पुल- इस नए पुल के बनने से बेगूसराय सहित संपूर्ण क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। यह विकासशील बिहार के आधुनिक आधारभूत ढांचे का प्रतीक होगा। राजेंद्र पुल के समानांतर बने इस पुल पर फ़िलहाल एक लेन से वाहनों का आना-जाना जारी है। जबकि दूसरे लेन का काम भी अब पूरा हो चुका है। पूरी तरह इस पुल के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों की दूरी दक्षिण बिहार से काफी कम हो जाएगी। जिससे लोगों को राजधानी पटना आने-जाने में बड़ी सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। जिसके तहत औंटा घाट से सिमरिया के बीच 6 लेन के नए गंगा पुल का निर्माण शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुल की आधारशिला रखी थी।ताइस ब्रिज के बनने से पटना से मोकामा व बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक 4 लेन सड़क की संपर्कता सुनिश्चित हो चुकी है। जबकि पटना से बख्तियारपुर के बीच 4 लेन सड़क पहले से चालू हो चुका है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बनी नई 4 लेन सड़क का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त को किया जाएगा। इस सड़क की कुल लम्बाई 44.60 किमी है। इसके निर्माण में 1899 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं।

पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री देंगे सौगात

विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वे जेसोर रोड से नोआपाड़ा-जय हिंद बिमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वे सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंदर और वापस मेट्रो की सवारी भी करेंगे।

भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच छठी उच्च स्तरीय बैठक हनोई में आयोजित हुई

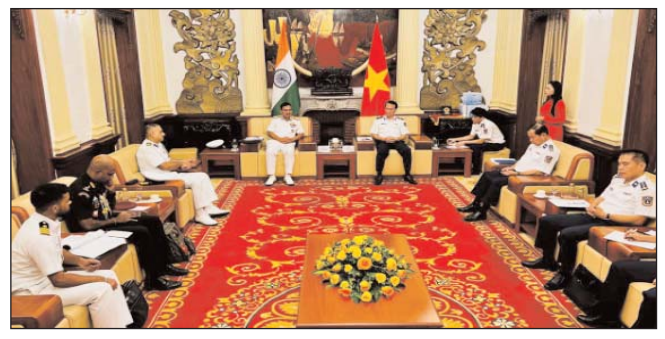

एजेंसी। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और वियतनाम तटरक्षक बल (वीसीजी) के बीच छठी उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम) तटरक्षक सहयोग पर 2015 के समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत 20 अगस्त, 2025 को वियतनाम के हनोई में आयोजित की गई। यह चर्चा समुद्री खोज एवं बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण कार्रवाई और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। बातचीत में तस्करी, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने सहित अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला और वियतनाम तटरक्षक बल के वाइस कमांडेंट मेजर जनरल वु ट्रुंग किएन ने की।

लोकशक्ति www.lokshakti.in

बीटीआई ग्राउण्ड शंकर नगर में लगी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी को मिल रहा शानदार प्रतिसाद

काटन, कोसा की साड़िया और सूट की महिलाएं जमकर कर रही खरीदी

पारंपरिक वस्त्रों की रेंज और ग्रामोद्योग उत्पाद बने आकर्षण का केन्द्र

रायपुर। शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में लगी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी को लोगों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट बुनकरों, हस्तशिल्पियों, माटी शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कोसा और काटन की साड़ियां, बेडशीट, ड्रेस मटेरियल, सूट, कॉटन बैग, कोसा शाल, जैकेट, बेलमेटल, काष्ठ-बॉस शिल्प, लौहशिल्प सामग्रियों को खरीदने के लिए प्रतिदिन लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। हस्तशिल्प और सजावटी सामग्रियां लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी है। घरों सजावट के लिए लोग इन्हें खरीद रहे हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामोद्योग की यह प्रदर्शनी 7 अगस्त राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू हुई थी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। हाथकरघा विभाग की ओर से इस प्रदर्शनी में विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्रियों पर अधिकतम 60 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। प्रदर्शनी में राज्य के बुनकरों एवं शिल्पकारों द्वारा तैयार विविध उत्पाद प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह-संचालक श्री श्याम धावड़े ने बताया कि प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर अपने पसंद के परिधान और वस्त्रों के साथ-साथ हस्तशिल्प सामग्रियों की खरीदी कर रही हैं। यहां गोदना शिल्प, शीसल शिल्प और हाथकरघा वस्त्रों में कोसा सिल्क, टसर सिल्क, कॉटन के ड्रेस मटेरियल, साडिय़ां, टुपट्टे, चादर, बेडशीट तथा खादी वस्त्रों और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित सामग्रियां ने लोगों को आकर्षित किया है। त्योहारों के सीजन में भारी छूट के साथ यह प्रदर्शनी लोगों के लिए एक सौगात है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विपणन संघ के सचिव श्री एम.एम. जोशी ने बताया कि ग्रामोद्योग के उत्पादों की प्रदर्शनी में खूब बिक्री हो रही है। लोग यहां लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में पहुंचकर किफायती दरों में मिलने वाले पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प और सजावटी सामग्रियों को खरीद रहे हैं।

धान खरीदी में बड़ा बदलाव : अब किसानों को सीधे बैंक खाते में मिलेगा भुगतान

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 25,000 किसान लाभान्वित होंग

बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान पाने के लिए सहकारी बैंकों और समितियों के चक्कर लगाने से निजात दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस खरीदी सत्र से राज्य सरकार ने धान का भुगतान सीधे किसानों के आधार-लिंक बैंक खातों में करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत पहले चरण में कोंडागांव, कोरिया और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों से होगी, और अगले साल से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान होने से किसानों को त्वरित और बिना किसी बाधा के पूरा पैसा मिल सकेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। अब किसानों को वही बैंक खाता उपयोग करना होगा, जो गैस सब्सिडी और अन्य योजनाओं के लिए पहले से लिंक है। इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब वे किसी भी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरी राशि निकाल सकेंगे, जबकि पहले समितियों के माइक्रो एटीएम से अधिकतम 10 हजार रुपये ही मिलते थे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं पर भरोसा तीनों में बढ़ोतरी होगी। पहले चरण में इस योजना से कोंडागांव के 22,755, कोरिया के 55,577, और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 25,000 किसान लाभान्वित होंगे।

भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले की जांच धीमी : संभागायुक्त ने रिपोर्ट न देने वाली टीमों पर जताई नाराजगी

रायपुर। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकॉनामिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में घोटाले के मामले में जांच की रफ्तार धीमी हो गई है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार को मुआवजा दावों और आपत्तियों की समीक्षा बैठक की, जहां केवल दो जांच टीमों ने ही रिपोर्ट पेश की। शेष दो टीमों द्वारा रिपोर्ट जमा न किए जाने पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

मुआवजा संबंधी अनियमितताओं को देखते हुए संभागायुक्त ने सभी किसानों से नए सिरे से दावे और आपत्तियां मंगवाए, जिनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है। इन मामलों की जांच के लिए चार जांच टीमों का गठन किया गया था, जिनमें अपर कलेक्टर ज्योति सिंह, उमाशंकर बंदे, निधि साहू और इंदिरा देवहारी शामिल हैं। सभी टीमों को पहले एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, जिसकी समय सीमा बाद में 15 अगस्त तक बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी दो टीमों ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जांच रिपोर्टों में हो रही देरी के कारण प्रभावित किसानों को न तो उचित मुआवजा मिल पा रहा है और न ही घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई हो पा रही है। अधिकांश किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें जमीन के बदले बहुत कम मुआवजा मिला है। संभागायुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कम मुआवजे से जुड़े मामलों में किसान संभागायुक्त न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। जबकि, मुआवजा घोटाले और प्रशासनिक गड़बड़ियों से संबंधित मामलों पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

राजस्व निरीक्षकों ने किया ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा था। संघ का कहना है कि समय-समय पर पत्राचार करने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है, जिससे शासन की उदासीनता झलकती है।दरअसल, संघ ने ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के सभी राजस्व निरीक्षक अब ऑनलाइन कामकाज नहीं करेंगे। विभाग के अन्य कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं ठप होने से आम जनता को सीधा असर झेलना पड़ेगा।नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति। नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति/भर्ती से भरने की व्यवस्था। मोबाइल, कंप्यूटर व इंटरनेट सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। ऑनलाइन मानचित्र बंटाकन अनुमोदन की समस्याओं का समाधान। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और अतिरिक्त प्रभार का भत्ता। सीमांकन व बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरणों की पूर्ववत समयावधि। सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित मांगों का निस्तारण।संघ ने जानकारी दी कि सीमांकन, नक्शा बंटाकन और अन्य ऑनलाइन कार्यों के दबाव के बीच राजस्व निरीक्षक असुरक्षा की स्थिति में कार्य कर रहे हैं। रिक्त पदों के कारण कई निरीक्षकों को एक साथ दो से तीन सर्कलों का भार उठाना पड़ रहा है, जिससे मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ गया है।

पीएम जनमन आवास योजना से पूरा हुआ सपना, पहारू राम ने कहा : नए घर ने दी जीवन की सबसे बड़ी खुशी

पीएम जनमन आवास योजना से पूरा हुआ सपना, पहारू राम ने कहाः नए घर ने दी जीवन की सबसे बड़ी खुशी

रायपुर। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत पंड्रापाठ के निवासी श्री पहारू राम वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे थे। बरसात में टपकती छत, सर्दियों की ठिठुरन और गर्मियों की तपन उनके परिवार के लिए हमेशा की मजबूरी रही। सीमित संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह गया था। वर्ष 2023-24 में उन्हें प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिली। समय पर राशि और सामग्री उपलब्ध होने से उनका मकान बनकर तैयार हुआ और आज वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित पक्के घर में रह रहे हैं।श्री पहारू राम भावुक होकर कहते हैं कि नए घर ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मेरा परिवार मौसम की मार से सुरक्षित है। यह घर हमारे लिए सुरक्षा और सम्मान की नई पहचान है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना घर स्वयं बना सकें और गरिमामय जीवन जी सकें।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान जल महोत्सव का होगा आयोजन : मंत्री

राज्य अलंकरण पुरस्कार में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत

रायपुर। जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान जल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अरपा महोत्सव, ईब महोत्सव, महानदी महोत्सव और इंद्रावती महोत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश आज जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नदियां हमारी सभ्यता और आस्था का केन्द्र रही है, जल महोत्सव से लोगों को प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ जल संरक्षण के प्रति भी भावनात्मक तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल पुरस्कार भी दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में बोधघाट वृहद् परियोजना, इन्द्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, शेखरपुर जलाशय एवं डांडपानी जलाशय परियोजना के संबंध में अद्यतन जानकारी ली। सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि निविदाकारों के द्वारा अनियमितता बरतनें पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 निविदाकारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति के बाद भी तकनीकी स्वीकृति नहीं मिलने के प्रकरणों में जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जलाशयों में जलभराव की अद्यतन स्थिति, विगत दो वर्षों से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रगति, जल जीवन मिशन, अमृत मिशन 2.0, स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उईके, मुख्य अभियंता सर्वश्री एस.व्ही. भागवत, प्रसून शर्मा, डी.के. बुम्मेरकर, जे.आर. भगत, आर.आर. सारथी, एस.के. टीकम, शंकर ठाकुर, के. एस. भंडारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन कामकाज बंद करेंगे राजस्व निरीक्षक, लंबित मांगों को लेकर बढ़ा असंतोष

संघ ने स्पष्ट किया है कि वे ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे,

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षकों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के समाधान में कोई प्रगति न होने से नाराज होकर ऑनलाइन कामकाज बंद करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने शासन को पहले ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण संघ के सदस्य शासन की उदासीनता से असंतुष्ट और परेशान हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि वे ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे, हालांकि विभागीय अन्य कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा क्योंकि सीमांकन, नक्शा बंटाकन और अन्य ऑनलाइन सेवाएं ठप हो जाएंगी। संघ की प्रमुख मांगों में नायब तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति, नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, ऑनलाइन मानचित्र अनुमोदन की समस्याओं का समाधान, रिक्त पदों पर भर्ती और अतिरिक्त प्रभार भत्ता शामिल हैं। इसके अलावा संघ ने सीमांकन और बंदोबस्त त्रुटि सुधार मामलों की पूर्ववत समय-सीमा बहाल करने, मानवीय भूल पर न्यायालयीन कार्रवाई के बजाय विभागीय स्तर पर समाधान और संवर्गों के विलय-मर्जिंग से जुड़ी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया है। संघ का कहना है कि ऑनलाइन कार्यों के बढ़ते दबाव और संसाधनों की कमी के चलते कई निरीक्षकों को दो से तीन सर्कलों का कार्यभार सौंपा जा रहा है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने उनकी मांगों पर जल्द गंभीरता नहीं दिखाई, तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने महिलाओं के साथ मनाया तीज मिलन समारोह

सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने की भागीदारी

कवर्धा। पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा 18 अगस्त को सामुदायिक भवन, पंडरिया में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र की 2500 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में महिलाओं के मनोरंजन हेतु सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था जिसमें उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विधायक भावना बोहरा ने प्रतियोगिता में विजयी महिलाओं को सम्मानित कर तीज पर्व की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दी, वहीं उनके साथ बड़े ही उत्साहव व विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता कर उत्साह के साथ उत्सव को मनाया।

कार्यक्रम में सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने वाली समूह की महिलाओं को 11,000 रुपए, द्वितीय स्थान को 5,100 रुपए, तृतीय स्थान को 2,100 रुपए एवं ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। इसी तरह एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान को 5,100 रुपए, द्वितीय स्थान को 2,100 रुपए, तृतीय स्थान को 1,100 रुपए एवं ट्रॉफी से पुरस्कृत कर बधाई व शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि तीजा पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा एवं नारी शक्ति के प्रतीक पर्व के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व नारी शक्ति, संवेदना, समर्पण और स्नेह का पर्व है जहाँ महिलाएं अपने पति के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए कठिन व्रत करती हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। तीजा में सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना लेकर शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में मान्यता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता इसी मान्यता का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ की डबल इंजन भाजपा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनान एक एलिए प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित कर रही है। तीज केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं और मूल्यों से परिचित कराता है। यह त्योहार सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें हर वर्ग और समुदाय की महिलाएँ एक साथ मिलकर उत्सव मनाती हैं। यह पर्व हमें नारी शक्ति, आत्मविश्वास और एकता का संदेश देता है।

महानदी पुल से कूदी महिला की लाश मिली, तलाशी के दौरान एक और महिला का शव बरामद

आरंग। पारागांव स्थित महानदी पुल से कथित तौर पर कूदने वाली विवाहित महिला स्वाति त्रिवेदी (27 वर्ष)का शव आज सुबह नदी में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के पास पुल के किनारे स्कूटी और दुपट्टा मिलने के बाद महिला की पहचान रायपुर के संतोषी नगर निवासी अजय त्रिवेदी की पत्नी स्वाति त्रिवेदी के रूप में हुई थी। स्वाति, जो ढाई माह की बेटी की मां थी, रक्षाबंधन मनाने मायके पारागांव आई हुई थी। रविवार को उसके पति और सास-ससुर बेटी से मिलने पहुंचे थे और फिर लौट गए थे। अगले दिन सोमवार सुबह स्वाति स्कूटी लेकर निकली, और कुछ ही देर बाद पुल के पास उसका सामान मिला। पहले दिन गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान नदी में एक और महिला का शव तैरता मिला, जिसकी पहचान महासमुंद जिले के बेमचा गांव की चंपा चंद्राकर (78 वर्ष) के रूप में हुई है। चंपा 15 अगस्त से अपने घर से लापता थीं। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना देकर पूछताछ के लिए बुलाया है और शव को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस स्वाति त्रिवेदी की मौत को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है और उसके पीछे के संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

संविधान के सिपाही सम्मान समारोह का भव्य आयोजन, 500 से अधिक युवा कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान

दुर्ग। जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण द्वारा संविधान के सिपाही सम्मान समारोह का भव्य आयोजन राजीव भवन दुर्ग में किया गया, जिसमें संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और जिला प्रभारी नरेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में तथा प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर की मुख्य अतिथ्यता में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से हुई और इस दौरान स्वर्गीय जावेंद्र बंजारे और प्रदीप पाटिल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि क्षितिज चंद्राकर ने सभी कार्यकर्ताओं को संविधान की प्रति भेंट करते हुए असंवैधानिक ताकतों के विरुद्ध संघर्ष और संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस संगठन देशभर में प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस आयोजन में 500 से अधिक युवा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष जयंत देशमुख के नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में पोस्टर विमोचन भी किया गया।

स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण

स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण

रायपुर।स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा मंत्रालय में अंबेडकर अस्पताल के नवनिर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसी के तारतम्य में आज स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अम्बेडकर अस्पताल परिसर के विभिन्न प्रस्तावित निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ट्रॉमा केयर सेंटर एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रस्तावित स्थलों का जायजा लिया तथा स्थल के चयन एवं उसकी उपयोगिता पर अम्बेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों व निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने एकीकृत मातृ-शिशु अस्पताल के प्रस्तावित स्थल का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने आगामी निर्माण कार्यों और विशेष रूप से 700 बेड क्षमता वाले एकीकृत अस्पताल के कार्य की प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज रायपुर के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर, लोक निर्माण विभाग एवं सीजीएमएससी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कैबिनेट ने अनुसूचित एवं अंत्योदय परिवारों को चना वितरित किए जाने का लिया निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में हुई। जिससे अंत्योदय परिवारों को हर माह चना ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी।

परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव ने बताया कि पिछले कई दिनों से गरीबो को चना देने की योजना विचाराधीन है, लेकिन इसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। प्रदेश में चना खरीदी के लिए कई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी तथा फर्म प्रयासरत थी। इस खरीदी को पारदर्शिता पूर्वक करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को जिम्मेदारी दी गई है। यह खरीदी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।

नवा रायपुर में आईटी सेक्टर के लिए 90 एकड़ भू-खण्ड आबंटित करने कैबिनेट का निर्णय

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आईटी सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसलिए राज्य युवा उद्यममियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जमीन आबंटित करने का निर्णय लिया है।

सेल ने सदैव सुरक्षा, हाउसकीपिंग और तकनीकी अनुशासन को दी प्राथमिकता : माथुर

सेल-बीएसपी में कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत कार्यशालाओं की शुरुआत

रायपुर। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विभाग द्वारा कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) के अंतर्गत विषयगत कार्यशालाओं की शुरुआत की गई। संयंत्र के मानव संसाधन विभाग के मुख्य सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री संदीप माथुर रहे। अपने संबोधन में श्री माथुर ने कहा कि सेल ने सदैव सुरक्षा, हाउसकीपिंग और तकनीकी अनुशासन के साथ-साथ कर्मचारियों की खुशी और मानसिक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के कार्यक्रम कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगे और सभी को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएंगे।कार्यशालाओं के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत एवं कार्य-संबंधी मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण, तनाव प्रबंधन, वित्तीय एवं कानूनी चिंताएँ, कार्य-जीवन संतुलन और पारिवारिक संबंध जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 17 फरवरी 2025 को निदेशक (कार्मिक) श्री के.के. सिंह द्वारा जूम मीटिंग के माध्यम से किया गया था, जिसमें सेल के सभी संयंत्रों एवं इकाइयों ने भाग लिया था। इसके बाद मेसर्स ईएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 19 फरवरी से 5 मार्च तक सभी पाँच इस्पात संयंत्रों में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। भिलाई में यह कार्यक्रम 24 से 26 फरवरी तक संपन्न हुआ था।इसके क्रम में अब 18 से 20 अगस्त तक विषयगत कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों के लिए परामर्श के लिए जाएँ या न जाएँ तथा गैर-अधिकारियों के लिए तनाव से शक्ति तक जैसे विषय रखे गए हैं। उद्घाटन दिवस पर विभिन्न विभागों से लगभग 300 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की।इस कार्यक्रम का समन्वय मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को स्वस्थ, संतुलित और सहयोगात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक (मानव संसाधन) सुश्री शालिनी चौरसिया और श्री सिकंदर इंदौरिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुश्री के. सुपर्णा ने प्रस्तुत किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एकलव्य स्कूलों के राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का किया

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एकलव्य स्कूलों के राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा 19 अगस्त और 20 अगस्त को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में प्रदेशभर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं भाग ले रहे हैं। विधायक श्री धरम लाल कौशिक ने प्रतियोगिता के शुभारम्भ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'खेलो इंडिया' के तहत पूरे देश में खेल के लिए जो माहौल बनाया है और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उससे पूरे प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। हमने फिर से खेल अलंकरण शुरू किया है जिससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है।

श्री साव ने खिलाड़ियों से कहा कि आप लोग जिस लगन के साथ खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको हरसंभव सुविधाएं मुहैया कराएगी। आपको खूब खेलना है, खूब पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी अपना पराक्रम दिखाते हैं।

विपरीत परिस्थितियों से जो लड़कर जीतता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। आपके अंदर जो जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है वह एक सच्चे खिलाड़ी का जज्बा है और इस जज्बे को हमेशा बनाए रखिए। खेल के क्षेत्र में अपना, अपने परिवार का, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। एकलव्य विद्यालयों की इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज, जूडो, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, योग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो और वालीबॉल की स्पर्धाएं होंगी।

दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी

रायपुर। मौसम विभाग के अनुसार ओड़िसा के समुद्रवर्ती तटीय क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होने से दक्षिण बस्तर में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. चन्द्रा के अनुसार ओड़िसा के तटीय क्षेत्र में बना कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते दक्षिण बस्तर में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इधर राजधानी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह से झमाझम वर्षा हो रही है। सूखे खेतों को पानी की आवश्यकता है। डॉ. चन्द्रा ने बताया कि दक्षिण तटीय ओडिशा पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 19 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे दरिंगाबादी (ओडिशा) से लगभग 50 किमी उत्तर-पश्चिम में दक्षिण आंतरिक ओडिशा पर केंद्रित था। इसके दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और अगले 12 घंटों के दौरान कमजोर होकर एक पश्चिमी चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

ईओडब्ल्यू और एसीबी चल रहे उधार में , पिछले 25 वर्षों से विभागीय नियुक्ति नहीं होने से अधिकारियों का टोटा

केन्द्र सरकार के निर्देश के बावजूद डिटेंशन सेंटर नहीं खुल पाया

रायपुर । राज्य में ईओडब्ल्यू तथा एसीबी नामक खुफिया एजेंसी में कर्मचारियों का टोटा है। यहां पर पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। लेकिन जैसी ही मूल विभाग में जाते हैं तो अपने साथ कर्मचारियों को भी ले जाते हैं। जिसके कारण यहां इन दोनों एजेंसियों का काम प्रभावित हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भ्रष्टाचार रोकने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी को प्रारंभ किया गया है। लेकिन यहां पर मौकापरस्त अधिकारी आते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शासकीय कर्मचारियों की धरपकड़ की जाती है। इसके पश्चात शासकीय अधिकारियों को कार्यालय एवं कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। वहीं शासकीय कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर उनकी धरपकड़ की जाती है। विभाग द्वारा सभी वर्ग के कर्मचारियों को रंगेहाथ पकड़ा जाता है, जिन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। इन अधिकारियों की नजर राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी रहती है, वे सरकार के नाक, कान होते हैं। ये अधिकारी मुख्यमंत्री के खुफिया विभाग के डायरेक्ट जानकारी देते हैं।

उधार में चल रहा विभाग : राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत इन दोनों विभाग को रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इसके मुखिया होते हैं, पिछले 25 साल से इसमें कोई भर्ती नहीं हुई है। जुगाड़ के हिसाब से जो अधिकारी अपने हिसाब से अधिकारियों को रिलीफ कराकर ले जाता है। पिछले डेढ़ दशक से यह काम चल रहा है। इस विभाग में रिफॉर्म करने की काफी कोशिश की जा रही लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा कार्रवाई करने के बाद प्रकरण का निपटारा कोर्ट में होता है, लेकिन प्रकरण चलने की अवधि में अधिकारियों को पदोन्नति तथा नियमित वेतनमान से वंचित होना पड़ता है।

नियमों को लेकर लगा पेच : ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली में सबसे बड़े पेच हैं। अधिकारियों के अनुसार संपत्ति के मूल्यांकन को लेकर इसमें कॉफी पेच है, यह नियम कॉफी पहले बनाया गया था, जो आज की स्थिति में अव्यवहारिक है। यदि कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले मकान अथवा भूखण्ड, ज्वेलरी खरीदता है तो आज के बाजार मूल्य पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसको लेकर अधिकारी-कर्मचारी कॉफी परेशान है। ईओडब्ल्यू के घेरे में आने वाले अधिकारियों का कहना है कि छापे पश्चात बार-बार बुलाया जाता है तथा उन्हें नगद देने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण वे परेशान हो जाते हैं। इधर कोर्ट में यह मामला चलता है, जिससे वे कोर्ट का चक्कर काटते रहते है, इसके पूर्व यहां पर ईओडब्ल्यू प्रमुख एक अधिकारी बने थे। उन्होंने लेन-देन कर कई सारे मामले निपटाए। इसमें अभियोजन को स्वीकृति दिलाने के लिए भी एक पेच लगा हुआ है, जिसके तहत यहां पर भार साधक मंत्री द्वारा ही अभियोजन की स्वीकृति के बाद ही कोर्ट में मामला चलता है। इसके कारण भी पेच लग जाता है। कई मामले विधि-विधायी विभाग में लंबित पड़े रहते हैं। जिन अधिकारी-कर्मचारियों पर प्रकरण चलता है वे सामाजिक और सार्वजनिक अपमान से बचने के लिए रिश्वत देकर अपनी जान बचाना चाहते हैं।

डिटेंशन सेंटर नहीं खोलने से, बंगलादेशियों की धरपकड़ प्रभावित : केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक नहीं खोला गया है। जिसके कारण बंगलादेशियों को धरपकड़ करने में पुलिस वालों के हाथ पैर फुल गए थे, पहले एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, उसके बाद जेल भेजा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह नहीं खोला गया, जिसके कारण पुलिस वाले परेशान हैं। इस समय छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गए हैं लेकिन एसीबी और ईओडब्ल्यू उधार पर चल रहा है।

बैगा बाहुल्य ग्रामों के पेयजल संकट को दूर करेगी छीरपानी जलाशय आधारित योजना

मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल तेज, कलेक्टर ने विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा को मूर्त रूप देने और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्रामों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने छीरपानी मध्यम जलाशय पर आधारित नई जल प्रदाय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से दलदली ग्राम सहित 20 से 30 गांवों और बैगा बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) को निर्देशित किया कि वे तत्काल स्थल निरीक्षण करें और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि कौन-कौन से गांव योजना से जुड़ेंगे और उनकी पेयजल आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छीरपानी मध्यम जलाशय में हर साल पर्याप्त जल भराव होता है और इसकी जल आवक भी पर्याप्त है, सिंचाई कार्य के बाद भी पेयजल के लिए आपूर्ति की जा सकती है। यही कारण है कि यहां से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति संभव है। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को भी तकनीकी परीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

दलदली प्रवास से शुरू हुई पहल, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तीन से चार माह पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतिम ग्राम दलदली का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें प्रमुखता से पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय कनाई नाला से जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी।

हालाँकि, जिला प्रशासन और विभागीय टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि कनाई नाला में केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। ग्रीष्मकाल में जल प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है, जिससे नियमित और टिकाऊ पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है।

यही कारण रहा कि कलेक्टर श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को व्यवहारिक रूप देने और स्थायी समाधान के लिए छीरपानी जलाशय पर आधारित नई योजना बनाने का निर्णय लिया।

65 ग्रामों के लिए 118.06 करोड़ की योजना प्रस्तावित : बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उपमुख्यंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासो से राज्य शासन को कुसुमघटा, बैजलपुर और राजा नवागांव सहित बोड़ला विकासखंड के 65 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए 118.06 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति की अंतिम चरणों में है। इस योजना के लागू होने पर पूरे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने पेयजल योजनाओं के साथ-साथ जिले की अन्य प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें प्रमुख रूप से महतारी सदन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पंचायतों के अधोसंरचना मद से स्वीकृत निर्माण कार्य शामिल थे।

सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी होंगे शामिल

रायपुर। सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल द्वारा आगामी 22 अगस्त से 2 सितम्बर 2025 तक विदिशा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत केंद्रीय नियंत्रण श्रेणी के पदों–सिपाही फार्मा, सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक, धर्म गुरु (जेसीओ), जेसीओ कैटरिंग, एजुकेशन हवलदार और हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर–की भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 को होगी।इन पदों के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने सेना द्वारा जून-जुलाई 2025 में आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) उत्तीर्ण किया है। रैली के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता, दस्तावेज़ों की जांच और चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।भर्ती में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र शीघ्र ही उनके ई-मेल पर भेज दिए जाएंगे। भर्ती स्थल पर प्रवेश केवल प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि और समय के अनुसार ही मिलेगा। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अभ्यर्थियों की दौड़ रात्रि 1 बजे से प्रारंभ होगी।रैली में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अधिसूचना अनुसार तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों को केन्द्र के समकक्ष मिलेगा महंगाई भत्ता

रायपुर। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। दो प्रतिशत की होगी वृद्धि, अब केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारी फेडरेशन संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

संपादकीय

चुनाव आयोग पर बेबुनियादी आरोप ना लगाये राहुल

कांग्रेस चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का बेबुनियादी आरोप ना लगाये यदि आरोप लगाये हैं तो घोषणापत्र देकर राहुल गांधी आगे की कार्रवाई में साथ देवें ना कि बेबुनियादी तरीके से लोकतंत्र के कार्य करने वाले आयोग पर आरोप लगाये। देश के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कानूनन चुनाव निकाय को मसौदा मतदाता सूची से गायब लोगों के नामों की अलग से सूची तैयार करने/साझा करने या किसी भी कारण उनके नाम न शामिल करने के कारणों को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अदालत को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का आग्रह करते हुए आयोग ने पूरक हलफनामे के साथ दायर अन्य जवाब में कहा- अधिकार के तौर पर वे ऐसी कोई सूची नहीं मांग सकते। अपने मामले की पुष्टि के लिए आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 10 व 11 का हवाला दिया।

मौसम तो आते जाते रहेंगे

तुमसे होकर दूर कहां नजर आएंगे।
अखबारों में खबर बनकर रह आएंगे।

हर तरफसिर्फअंधेरा ही अंधेरा है।
अंधेरी राहों में हम कैसे गुजर पाएंगे।।

आरजुएं तमन्नाएं अब कुछ भी नहीं,
जर्रा हैं हम हवाओं में बिखर जाएंगे।।

तीर आसमान की तरफमत चलाना
वो तेरी तरफही फिर लौटकर आएंगे।।

ख्वाहिश है आखरी बार दरस की तेरे
कल हम न जाने किस तरफजाएंगे।।

ये सजर है तेरे ही गांव का शायद,
इजाजत हो थोडी देर ठहर जाएंगे।

ख्वाहिश आखरी बार दरस की तेरे
कल हम न जाने किस ओर जाएंगे।।

मौसम तो आते जाते रहेंगे संजीव
हम यादों के बन इक मंजर जाएंगे।

संजीव ठाकुर,

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra- Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल सिकल सेल के आनुवांशिक संचरण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है।

सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ज़ोर इसी के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023 में एनएससीईएम की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जाँच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या-आधारित आनुवंशिक जाँच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक एससीडी के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है।

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च-व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95त्न मामले केवल पाँच राज्यों–ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र–में केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक

उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

स्क्रीनिंग प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक उपकरणों को लगाया गया है। शुरुआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति किट लागत ?100 से घटकर ?28 हो गई है। इस पहल ने एससीडी के लिए लागत-प्रभावी और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएँ सुनिश्चित की हैं।

इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; यह एससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुँच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रॉक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होती है।

यह मिशन सिकल सेल रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीतियों के रूप में आनुवंशिक परामर्श और जन जागरूकता पर भी ज़ोर देता है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गए हैं, जो परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर, पंद्रह स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये संस्थान प्रसवपूर्व निदान और गंभीर सिकल सेल रोग जटिलताओं के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जोखिम वाले परिवारों को विशेष परिचर्या सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सिकल सेल रोग प्रबंधन की जटिलताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए गए हैं।

मिशन की सफलता संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक आयामों का समाधान करते हुए समग्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान-आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत-प्रभावशीलता और रोगी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

हालांकि इस मिशन की अब तक की उपलब्धियाँ बेहद सराहनीय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अब मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अब मिशन का तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण के विस्तार पर होगा। सामुदायिक स्तर के मंचों का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक वाहक और रोगग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या और सहायता प्राप्त हो। उन्नत अनुसंधान प्रयास मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस मिशन की असली भावना इसके आदर्श हमारे संघर्षकर्ताओं को साथ, हमारे उत्तरजीवियों को संबल, और हमारे योद्धाओं को समर्थन में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्तस करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पंर है।

जैसे-जैसे भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को न सहना पड़े।

सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई सिर्फ़ एक आनुवंशिक रोग से लड़ने तक सीमित नहीं है–यह हाशिए पर रहने वाले हमारे देश के समूहों के लिए समानता, सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता है। मीना जैसी महिलाओं के अनुभवी मार्गदर्शन में, यह मिशन लक्षित स्वास्थ्य सेवा पहलों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो जनजातीय स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आइए, इस अभूतपूर्व प्रयास का जश्न मनाएं और एक स्वस्थ, अधिक समावेशी भारत के निर्माण के अपने संकल्प को दोहराएं। **लोकशक्ति।**

सूदखोरी के मामले में विस्तृत जांच और सख्त कानून जरूरी!

अभिमनोज

सूदखोरी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक-मानसिक उत्पीड़न का व्यवस्थित तंत्र है। गरीब और मजबूर तबके का शिकार बनाकर अत्यधिक ब्याज वसूला जाता है, धमकियां दी जाती हैं, अपमान कराया जाता है और कई बार पीड़ित आत्महत्या तक मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ न्यायिक निगरानी, राज्यस्तरीय कड़े कानून और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लेंडिंग पर सख्त नियमन–सभी एक साथ काम करें, तभी वास्तविक राहत मिलती है।सूदखोरी का इकोसिस्टम तभी टूटेगा जब पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अदालत की सतर्क निगरानी, राज्य-केंद्र के समन्वित क़ानून, और ऋद्ध-आधारित डिजिटल नियमन एक साथ काम करेंगे। रायपुर प्रकरण जैसे मामलों में कड़ी लेकिन निष्पक्ष जांच, संपत्ति जब्ती और त्वरित ट्रायल के संदेश से ही स्थानीय नेटवर्क हतोत्साहित होंगे। दूसरी ओर पीड़ितों के लिए कानूनी-मानसिक सहायता और औपचारिक ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है–वरना चक्रव्यूह बदलकर फिर लौट आता है।

रायपुर का ताज़ा घटनाक्रम और बड़े सवाल छत्तीसगढ़ में चर्चित तोमर बंधुओं पर छापों में नकदी, गहने, कथित अवैध हथियार और ऋण से जुड़े दस्तावेज़ मिलने की खबरों के बाद मामला संगठित अपराध की दिशा में बढ़ा। दोनों इतिहास-शीटर भाई फरार बताए गए और पुलिस ने इनाम घोषित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब्तगी और तलाशी के दावे सामने आए जबकि हाईकोर्ट के पेज पर भी तोमर बंधुओं को अदालत में हाज़िर होने के निर्देश का उल्लेख दर्ज है, जो न्यायिक सतर्कता की ओर संकेत करता है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित सूदखोर तोमर बंधुओं की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की, इस दौरान अदालत ने सात एफआईआर दर्ज करने पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

इस मामले में हाईकोर्ट ने दर्ज सात एफआईआर पर सवाल उठाते हुए रायपुर एसपी से पूछा है कि- किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है, अदालत ने उनसे व्यक्तिगत शपथ-पत्र के साथ दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

उल्लेखनीय है कि रायपुर के तेलीबांधा और पुरानीबस्ती थाने में सूदखोर वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर एक्सटार्शन और सूदखोरी का केस दर्ज किया गया, पुलिस ने उनके घर में दबिश दी, जहां चेक और जमीनों के दस्तावेज मिले, इस कार्रवाई में यह मामला सामने आया कि- यह आर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ प्रकरण है.

इस मामले में पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग-अलग सात एफआईआर दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी, तो वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए.

पुलिस के हवाले से खबरें हैं कि रोहित ने अपनी पत्नी के नाम से ऑफिस खोला था, जहां से सूदखोरी का धंधा ऑपरेट होता था, इस मामले में दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों की जानकारी देने पर रायपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है.

उधर, पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए तोमर बंधुओं ने अपने एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की, जिसकी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने पुलिस पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि- उन्हें सूदखोरी और आर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे केस में फंसाया गया है!

डेटा जो तस्वीर साफकरता है

भारतीय बैंकिंग तंत्र में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों का मौद्रिक मूल्य स्न्ड्ढ25 में तीन गुना बढ़कर ?36,014 करोड़ पहुँचा, भले ही मामलों की संख्या घटी हो। विश्लेषण बताता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ पुराने प्रकरणों की पुनर्वर्गीकरण का असर भी शामिल है, फिर भी loan-linked और डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रही हैं। यह प्रवृत्ति अनौपचारिक उधारी और सूदखोरी के जाल के लिए उर्वर जमीन बनाती है क्योंकि औपचारिक चैनलों में भरोसा कमज़ोर पड़ता है।

राज्य कानून और हालिया सख्ती

कई राज्यों ने सूदखोरी पर लगाम कसने को अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। गुजरात में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत सूदखोरों की संपत्तियां जब्त कीं–चार मकान, दो प्लॉट और एक SUV–जिन पर मनी-लेंडर्स एक्ट और संगठित अपराध कानून के तहत कार्रवाई हुई। यह दृष्टांत बताता है कि लाइसेंस, ब्याज-दर और वसूली तरीकों पर उल्लंघन होने पर संपत्ति जब्ती जैसे कड़े कदम भी संभव हैं।

कर्नाटक ने 2004 के अत्यधिक ब्याज निषेध कानून में 2025 में संशोधन आगे बढ़ाया, जिससे अत्यधिक ब्याज वसूली पर दंडात्मक प्रावधान और प्रवर्तन सुदृढ़ हों। महाराष्ट्र में 2014 का मनी-लेंडिंग रेग्युलेशन एक्ट प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में हाल में नियमों के माध्यम से निजी साहूकारों के लिए दरें सार्वजनिक करने और लाइसेंस प्रदर्शित करने जैसी पारदर्शिता बाध्यताएँ बढ़ाई गईं। ये कदम पीड़ितों को कानूनी सहारा और साक्ष्य जुटाने में मदद करते हैं।

डिजिटल लेंडिंग और ऐप आधारित सूदखोरी का नया मोर्चा

RBI ने 2 सितंबर 2022 के दिशा-निर्देशों से डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर ग्राहक-सुरक्षा, डेटा-गोपनीयता, शुल्क-पारदर्शिता और शिकायत निवारण को बाध्यकारी बनाया। 2025 में इस ढांचे पर अनुपालन और CIMS जैसी निगरानी पहलों पर जोर बढ़ा, ताकि अधिकृत-बनाम-अनधिकृत ऐप्स की पहचान स्पष्ट हो और डिफॉल्ट-लॉस गारंटी जैसे प्रबंध नियंत्रित रहें। यह सूदखोरी के डिजिटल रूपों पर नकेल कसने की केंद्रीय कड़ी है। द्वह्ल

राष्ट्रीय विधायी पहल की दिशा

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट BULA यानी Banning of Unregulated Lending Activities बिल–अनधिकृत उधारी पर प्रतिबंध, दंड और प्रवर्तन प्राधिकरण के प्रावधान–पर सार्वजनिक विमर्श चल रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे उपभोक्ता-सुरक्षा के लिए ज़रूरी मानते हैं, तो कुछ इसे राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप बताकर सुधारों की मांग करते हैं। इसका सार यह है कि अनियमित उधारी पर एक समेकित, स्पष्ट और सुसंगत राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत व्यापक सहमति पा रही है।

हाईकोर्ट द्वारा बहु-FIR की वैधानिकता, एकत्र साक्ष्यों की विश्वसनीयता और संगठित अपराध के तत्वों पर राज्य पुलिस से शपथ पत्र सहित जवाब माँगना–यह सब न्यायिक समीक्षा की स्वस्थ परंपरा को दिखाता है। ऐसी निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि कठोर दंड तभी लागू हों जब जांच निष्पक्ष, अनुपातिक और साक्ष्य-आधारित हो। रायपुर प्रकरण में भी अदालत की पूछताछ यही संदेश देती है कि सख्ती और प्रक्रिया-न्याय दोनों साथ-साथ चलें।

सामाजिक प्रभाव और पैटर्न – व्यापारियों और किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ते कर्ज़, अत्यधिक ब्याज और वसूली-धमकियों की भूमिका बार-बार उभर रही है–गुजरात, लखनऊ और ओडिशा जैसे हालिया मामलों ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया है। ये घटनाएँ केवल निजी त्रासदी नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति की विफलताओं का दर्पण हैं–वित्तीय साक्षरता की कमी, औपचारिक ऋण की सीमित पहुँच और कमजोर प्रवर्तन इसका त्रिकोण है।

जांच कैसे हो ताकि पीड़ित को वास्तविक न्याय मिले प्रथम चरण में लेन-देनों का फॉरेंसिक नक्शा तैयार हो–चेक, प्रॉमिसरी नोट, बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप-कॉल लॉग, तक्क-ट्रिगरिंग और सीसीटीवी–ताकि उधारी का पैटर्न, ब्याज-दर और धमकी-वसूली के सबूत बनें।

उधारी चक्र के 'कलेक्टर' और 'फाइनेंसर' की भूमिका अलग-अलग पहचान कर द्धक्क्ट, राज्य स्र्शठ्ठद्द4-द्यद्गठ्ठस्रद्गह्म्ह्य ्रष्ह्ल और संगठित अपराध कानूनों का समवर्ती प्रयोग किया जाए। गुजरात की जब्ती कार्यवाही जैसी मिसालें केस-बिल्डिंग की ठोस रणनीति देती हैं। पीड़ित-केंद्रित स्नढ्ढक्र ड्राफ्टिंग–ब्याज-दर, वसूली तारीखें, धमकी के प्रकार, साक्ष्य-सूची–को स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाया जाए, ताकि अदालत में केस टिके।

जिला स्तर पर Fast-track अदालतें–ऐसे मामलों में 90–120 दिन की तय समयसीमा–ताकि लंबे मुकदमों के कारण समझौते और दबाव न बढ़ें।

नीतिगत सिफारिशें जो तुरंत लागू की जा सकती हैं लाइसेंस और डिस्क्लोज़र व्यवस्था का सार्वजनिकीकरण

सभी लाइसेंसी साहूकारों के लाइसेंस नंबर, अधिकतम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और शिकायत निवारण अधिकारी का नाम-नंबर थाने, तहसील और ग्राम पंचायत भवन में प्रदर्शित करने की बाध्यता। महाराष्ट्र ने दरें प्रदर्शित करना और लाइसेंस दिखाना अनिवार्य किया–इसे राष्ट्रीय मानक बनाया जा सकता है। ब्याज सीमा और दंड की एकरूपता

कर्नाटक जैसे राज्यों के कानूनों में संशोधन के बाद दर-सीमा और दंड स्पष्ट हुए हैं। केंद्र एक मॉडल एक्ट जारी कर राज्यों को समान मानक अपनाने को प्रेरित करे।

डिजिटल लेंडिंग की 'व्हाइट-लिस्ट' और 'रेड-लिस्ट'

RBI दिशा-निर्देशों के आलोक में अधिकृत ऐप्स की सार्वजनिक सूची अपडेट हो और अनधिकृत ऐप्स पर प्लेटफ़ॉर्म-स्तर पर तत्काल ब्लॉक, साथ ही कॉल-सेंटर आधारित उत्पीड़न पर पुलिस की संयुक्त टास्क-फोर्स। क्चह्र को सहयोगी-संघीय ढाँचे में लाना

मसौदा बिल में राज्यों की लाइसेंसिंग शक्तियों और प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय का ठोस डिज़ाइन शामिल हो ताकि अधिकार-क्षेत्र टकराव न हो और ज़मीनी प्रवर्तन तेज़ हो।

पीड़ित सहायता और पुनर्वास

जिला-कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर Debt Distress Helpline, निःशुल्क वकालतनामा, और 'ऋण-समझौता क्लिनिक' जो वैध और अवैध उधारी की पहचान कराने में मदद करें।

व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर क्या करें

किसी भी उधारी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर से पहले फोटोकॉपी रखें, दर और शुल्क लिखित में मांगें, और भुगतान डिजिटल माध्यम से करें ताकि ट्रेल बने रहे।

धमकी, मारपीट, सोशल मीड पर अपमान–इनमें से किसी का भी स्क्रीनशॉट/रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें; यह IPC और आईटी एक्ट के तहत साक्ष्य बनता है।

थाने में शिकायत के साथ जिला रजिस्ट्रार ऑफ मनी-लेंडर्स या कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराएँ, ताकि प्रशासनिक और आपराधिक दोनों चैनल सक्रिय हों।

यदि उधारी ऐप से है तो RBI की गाइडलाइन के अनुरूप कंपनी का नाम, NBFC पार्टनर और शिकायत अधिकारी पहचानें; 'अनधिकृत' दिखने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट करें। *यह निजी विचार है।*

आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति बननें अग्रसर भारत।

पिछले 11 वर्षों में भारत की चौतरफा विकास की गति को पूरा विश्व अपनी आंखों से देख रहा है। अब भारत एशिया का बड़ी शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है। चीन के बाद भारत बहुत बड़ी सामरिक शक्ति भी बन चुका है। भारत ने अन्न तथा दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट लोहे से बनी सामग्रियां एवं सामरिक महत्व के हवाई जहाज पानी के जहाज एवं अन्य आवश्यक अस्त्र-शस्त्र निर्माण करने में अग्रणी भूमिका का संचालन शुरू कर दिया है। अब भारत शस्त्रों का निर्यातक भी बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रुस से भारत ने कच्चा तेल आयात कर उसे भी परिष्कृत करने के बाद दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया और यह बात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी जिसके फलस्वरुप उसने 25 से लेकर 50त्न तक आयात शुल्क लगाकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। जिससे भारत तथा अमेरिका के रिश्तो में अस्थाई रूप से खटास आ गई है।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अथक प्रयास करने के पश्चात आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कार्यप्रणाली इसी सोच के साथ आगे बढ़ाई थी कि भारत अब एक समृद्ध, शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर कर आया है। इसी तारतम्य में 1952 से प्रारंभ की गई पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि, उद्योग, विज्ञान और स्वास्थ्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सोच को मूर्त रूप दिया गया था। समय समय मैं सरकारें बदलती रहे और भारत विकास की ओर धीरे-धीरे बढता रहा। आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक स्थिति में जबरदस्त विकास किया है, भारत विश्व में पांचवी आर्थिक स्थिति बन चुका है दूसरी तरफविज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में भी अहम स्थान रखता है। सामरिक तौर पर भी भारत की सेना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान रखती है ।अब पाकिस्तान या चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सीधा भारत पर आक्रमण कर सकें। भारत ने विकास कर यह साबित कर दिया है भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है और अब किसी भी विषम परिस्थिति मैं भारत सीना तान कर खड़ा हुआ हैद्य

मैं किसी पार्टी विशेष का पक्षधर नहीं हूं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ,अटल बिहारी वाजपेई, डॉ मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वैश्विक पटल पर एक सम्मानजनक इस स्थिति में ला खड़ा किया हैद्य अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर कर उसका विभाजन कर बांग्लादेश नामक नए देश का जन्म करवाया थाद्य

पर मैं यहां बात विकास के वास्तविक धरातल और देश में गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन की करना चाह रहा हूं. हमारा देश अभी भी गरीबी ,बेरोजगारी ,भुखमरी, असमानता, अंधविश्वास, आडंबर और धार्मिक कट्टरपंथ का सामना करते हुए उस गति से विकास नहीं कर पा रहा है जिसके लिए वह अत्यंत समर्थ है। आज भारत की धमक अमेरिका से लेकर जापान तथा अफ्रीकी देशों में भी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत अमेरिका फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ब्राजील इजरायल और सऊदी अरेबिया देश के अनेक राज्यों के राष्ट्रीय प्रमुख हुक्मरानों ने दिल खोलकर किया है, नरेंद्र मोदी की वैश्विक हैसियत इसी बात से पता चलती है कि बाहुबली अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका ऑटोग्राफलेने की गुजारिश की है और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्र प्रमुख ने उनके चरण छूकर उनका अभिवादन किया ,यह संभवत चमत्कारिक प्रभाव भारत के शक्तिशाली होने एवं वैश्विक शांति के प्रति देश की प्रतिबद्धता के कारण ही हुआ है।

यह निजी विचार है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में बाल स्वास्थ्य पर 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन

आयुर्वेद की बाल-देखभाल प्रणाली कौमारभृत्य से स्वस्थ बालक, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है: केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

पीआईबी

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) ने आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में ÷आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं कल्याण प्रबंधन÷ विषय पर अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया। 18-19 अगस्त 2025 तक आयोजित इस दो दिवसीय संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात आयुर्वेद विद्वानों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और छात्रों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगो?ठी के दौरान हुए विचार-विमर्श में बच्चों में रोग प्रबंधन और स्वास्थ्य संवर्धन पर विशेष ध्?यान दिया गया, जिससे बाल स्वास्थ्य के प्रति आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण की पुष्टि हुई। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित संदेश के माध्यम से अपने समापन संबोधन में कहा कि इस संगोष्ठी के परिणाम भारत के बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा ढांचे को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की कौमारभृत्य शाखा में निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक दृष्टिकोणों के समन्?वय के साथ बाल स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन लाने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में साझा

किया गया सामूहिक ज्ञान, स्वस्थ बालक, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए शोध सहयोगों और व्यावहारिक मॉडलों को प्रेरित करेगा।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस संगोष्ठी ने बाल चिकित्सा आयुर्वेद में शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए एक मानक स्थापित किया है। उन्होंने साक्ष्य-आधारित सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के साथ समायोजित करने के लिए सहयोगात्मक अध्ययनों की आवश्यकता दर्शाई।

वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बाल चिकित्सा कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरएवी और एआईआईए की भी प्रशंसा की। आरएवी की निदेशक डॉ. वंदना सिरोहा ने अपने समापन संबोधन में कहा कि संगोष्ठी की सफलता आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी को पोषित करने के लिए आरएवी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि शोधपत्र और पोस्टर प्रस्तुतियों में युवा विद्वानों की सक्रिय भागीदारी ने बाल चिकित्सा आयुर्वेद के उज्ज्वल भविष्य को प्रदर्शित किया है।

22-23 अगस्त को रानी सती मंदिर में 49वाँ भादों अमावस्या मेला

लोकशक्ति

रायपुर। राजा तालाब स्थित श्री रानी सती मंदिर में आगामी 22 व 23 अगस्त 2025 को 49वाँ भादों अमावस्या मेला श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष किशोर ड्रोलिया ने बताया कि इस बार की तैयारियाँ विशेष रूप से आकर्षक और भव्य हैं। कोलकाता से आए 11 अनुभवी सजावट कलाकारों द्वारा सजावट में लगभग 31,000 सुनहरे (गोल्डन) एवं रजत (सिल्वर) छतर लगाए जा रहे हैं। इन्हें लाल एक्रेलिक शीट, रेशमी गोटों तथा कोलकाता कुमाटोली की प्रसिद्ध चलचित्र कला से सुसज्जित किया गया है।

मंदिर परिसर के विभिन्न देवालयों में भी विशेष श्रृंगार किया जा रहा है।भगवान शंकर के मंड को ताजे फूल-पत्तियों से सजाया गया है। हनुमानजी के मंड को रेशमी गोटों और पुष्पों से अलंकृत किया गया है।दादी माँ के त्रिशूल का भव्य श्रृंगार श्रद्धालुओं का मन मोह लेगा।इस वर्ष प्रथम दिन 22 अगस्त को विशेष आकर्षण दादीजी को अर्पित होने वाली 51 सवामणि रहेगी, जिसकी तैयारी मंदिर समिति की देखरेख में की जा रही है।

कार्यक्रम विवरण - 22 अगस्त (शुक्रवार) प्रातः 11:00 बजे - पंचामृत स्नान व ध्यान संध्या 7:00 बजे - श्रृंगार दर्शन रात्रि 8:30 बजे - ज्योति पूजन रात्रि 9:00 बजे - भजन संध्या रात्रि 1:00 बजे - छप्पन भोग प्रसाद वितरण,पुनः भजन उत्सव एवं प्रभाती आरती प्रातः 4:00 बजे तक । 23 अगस्त (शनिवार) प्रातः 7:00 बजे - जात धोक पूजन अपराह्न 2:00 बजे - मंगल पाठ संध्या 5:00 बजे - भजन संध्या एवं मेला

रात्रि 9:30 बजे - छप्पन भोग प्रसाद वितरण एवं महाआरती। भजन संध्या आयोजन का मुख्य आकर्षण कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्याम अग्रवाल एवं भजन गायिका राधा श्री की भक्ति संध्या होगी, जिनके सुमधुर भजन वातावरण को भक्तिमय बनाएँगे।

हजारों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए मंदिर समिति द्वारा सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। समिति ने श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि वे परिवार सहित इस पुण्य अवसर पर सम्मिलित होकर दादीजी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

उत्तरकाशी में हाल ही में आई बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के बाद रवाना होते हुए।

संसदीय कार्य मंत्रालय सेवा भावना को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है

पीआईबी

संसदीय कार्य मंत्रालय अधिकारियों में सेवा भाव और उत्तरदायित्व की भावना को मज़बूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस प्रशिक्षण ने अधिकारियों को अपनी भूमिकाओं के प्रति अधिक जागरूक और जनता की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण आयोग द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में जनसेवा की भावना और उनके द्वारा किए गए कार्य के प्रति संतुष्टि का भाव जागृत करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) को प्रशिक्षित किया गया है। यह मास्टर प्रशिक्षक अपने मंत्रालय/विभाग के 30 से 35 अधिकारियों के बैच को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में परस्?पर संवादात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: द्व. स्थिति परक अभ्यास, जिसमें प्रतिभागी सामूहिक रूप से अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाते हैं

(कर्मयोगी तरीके से काम करने का परिचय)। ii. विस्तृत टीम डिजाइन अभ्यास जिसमें प्रतिभागी अपनी वर्तमान भूमिकाओं और अपने अनुभाग में कार्य तथा विभाग और बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति अपने योगदान पर विचार करते हैं।

उत्कृष्ट सेवा के लिए 13 विद्युतकर्मी राज्य स्तर पर पुरस्कृत

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मुख्यालय परिसर में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 विद्युत कर्मियों को अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव (आईएएस) ने नगद, पदक एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया। तीनों पॉवर कंपनियों के उत्कृष्ट कर्मियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया से किया गया था।

कंपनी मुख्यालय में आयोजित समारोह में जनरेशन कंपनी के श्री सतीश कुमार रस्तोगी, सहायक अभियंता को मड़वा विद्युत गृह 2 के कोल मिल क्र. 2-एच के प्लेनेटरी गियर बाक्स में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने, श्री आर.के. कौशिक, कार्यपालन अभियंता, एचटीपीएस, कोरबा पश्चिम को 4म210 एवं प्रस्तावित 2म660 मेगावॉट की नवीन परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।

ट्रांसमिशन कंपनी के श्री त्रिभुवन जंघेल, परिचारक श्रेणी-एक (लाइन) अति उच्च दाब (संधारण) संभाग, भिलाई को 220 केवी खेदामारा-ठेलकाडीह सर्किट-2 में कंडक्टर हार्डवेयर फेल होने से बाधित

विद्युत आपूर्ति को बहाल, श्री इंजोर कुमार साय, कार्यपालन अभियंता, (निर्माण) संभाग, कोरबा को सघन वन क्षेत्र को बायपास करते हुए 132/33 केवी उपकेन्द्र जनकपुर को ऊर्जस्कृत करने, श्री गणेशराम जायसवाल, कार्यपालन अभियंता (निर्माण) संभाग, बिलासपुर को अति उच्च दाब उपकेन्द्र मस्तुरी एवं धरदेही के लिये 400 केवी लाईन के निर्माण एवं कोंडातराई-जुर्डा 132 केवी लाइन के निर्माण कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए पुरस्कृत किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के श्री अविनाश कुमार दुबे, सहायक अभियंता (बघेरा उपसंभाग) को बकाया राशि में 48 प्रतिशत की कमी तथा ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट में 5 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत लाने, श्री नितेश चन्द्र दुबे तकनीशियन नगर संभाग दक्षिण रायपुर ने आंधी-तूफान के कारण 33 केवी के 9 फीडरों में ब्रेक-डाउन के कारण 12 उपकेन्द्रों एवं 20 उच्चदाब उपभोक्ताओं की बाधित विद्युत व्यवस्था को अल्पसमय में बहाल करने के कारण पुरस्कृत किया गया। इसी तरह केंद्रीय कार्यालय स्तर पर 6 कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। जनरेशन कंपनी से श्री पंकज जायसवाल, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 8.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत ऋण की बकाया राशि को 7.48 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर रिफायनेंस करवाने, श्री बादल वर्मा, सहायक अभियंता (सी.एण्ड आर.ए) को वर्ष 2025-26 की पूंजीगत निवेश योजना याचिका में खर्च की जानकारी का संकलन करने के लिए पुरस्कृत किया गया। ट्रांसमिशन कंपनी के श्री यू.आर. मिर्चे, अधीक्षण अभियंता (लाइन) को विधानसभा व लोकसभा प्रश्नों के उत्तर एवं छत्तीसगढ़ महालेखाकार के ऑडिट-पैराओं का उपयुक्त जवाब समय-सीमा में प्रेषित करने, श्रीमती रेखा शर्मा, सहायक अभियंता (भार प्रेषण केन्द्र) को ट्रांसमिशन लॉस की गणना से संबंधित सभी आंकड़ों को दुरूस्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के श्री दुर्गा चरण पटेल कार्या. सहा. श्रेणी-दो को निविदा संपादित करने, न्यायालयीन प्रकरणों, विधानसभा प्रश्नों की जानकारी को समय सीमा में उपलब्ध कराने, श्री प्रभाकर उराव, सहायक अभियंता (राजस्व) को डिजिटल एवं ऑनलाइन भुगतानों तथा सैप बिलिंग मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि व उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण करने हेतु पुरस्कृत किया गया।

भगवान की लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है - पंडित मनोज शुक्ला

(56 भोग की शुरूआत कैसे हुई बताया पंडित शुक्ला ने)

लोकशक्ति संवाददाता। चौहान ग्रीन वैली जुनवानी में रमेश कुमार तिवारी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमदभागवत कथा में ज्योतिषी एवं भगवताचार्य महामाया मंदिर रायपुर के पंडित मनोज शुक्ला जी महाराज ने आज कथा में श्रीकृष्ण बाल लीला, पुतना वध, ऊखल बंधन , माखन चोरी , गोपाल बनना , मोरपंख बंशी धारण करना , कालिया नाग मर्दन, अकासुर, बकासुर वध तथा गोवर्धन पूजा की कथा विस्तार से श्रद्धालुओं को सुनाई।

पंडित मनोज शुक्ला ने कहा कि भगवान की लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं। भगवान कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की है । बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते यशोदा मां के पास उनकी हर रोज शिकायत आती थी। मां उन्हें कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुरा के खाया करते हो, तो वह तुरंत मुंह खोलकर मां को दिखा दिया करते थे कि मैंने माखन नहीं खाया। एक दिन माता यशोदा को अपने मुख मे पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। कन्हैया ने खेलते खेलते तालाब में भयंकर विषधारी कालिया नांग का मर्दन किया और गोकुलवासियों को भय से मुक्त किया।

एक दिन भगवान कृष्ण गैया चराने अपनी सखाओं और गोप-ग्वालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए थे, वहां पर गोपिकाएं विविध प्रकार का भोजन रखकर नाच गाने के साथ उत्सव मना रही थीं। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के ही दिन देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रोज यज्ञ

कहते हैं। इससे प्रसन्न होकर इंद्र व्रज में वर्षा करते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उनसे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण ही वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानते हुए व्रज में गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राहि-त्राहि होने लगी।

सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का अहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। गोवर्धन पर्वत को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किये गए।

माता यशोदा भगवान कृष्ण को 8 बार भोग खिलाती थी और 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन को उठाये रखा, इसलिए 7 दिन बाद इंद्र का अहंकार दूर होने और बारिश रुकने के बाद उन्हें 8 दिन के हिसाब से 56 प्रकार के भोग लगाए गए तब से 56 भोग लगाए जाने की शुरूआत हुई।

भागवताचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने आगे कथा मे बताया कि कंस द्वारा श्रीकृष्ण को मारने के लिए अनेक शक्तिशाली राक्षसों को भेजा लेकिन तमाम प्रयास असफल होने के बाद कंस ने अक्रूर जी को मथुरा में उत्सव के बहाने कृष्ण और बलराम को लेने भेजा। गोकुलवासियों के मना करने के बाद भगवान कृष्ण उन्हें समझाकर मथुरा पहुंचते हैं। कंस दोनों को मारने की योजना बनाकर मदमस्त हाथी छोड़ देता है। भगवान उसका वध कर देते हैं। भगवान कृष्ण कंस को ललकारते है और उसके सिहासन पर चढ़कर कंस को नीचे गिराते हैं व उनसे युद्ध कर उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं से दुष्टों का अंत किया व अपने भक्तों की रक्षा की। छोटे छोटे बच्चों ने बाल गोपाल कन्हैया का रूप धारण कर लीला झांकी दिखाया। संगीत के साथ सुंदर भजनों ने सबका मन मोह लिया। मुख्य यजमान श्रीमती काजल - आशीष तिवारी ने आरती पश्चात प्रसादी वितरण किया।

22-23 अगस्त को रानी सती मंदिर में 49वाँ भादों अमावस्या मेला

केशरी शिक्षा महाविद्यालय खोखरा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

लोकशक्ति

जांजगीर चांपा / भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर केशरी शिक्षण समिति, खोखरा में देशभक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। संस्थान प्रांगण देशप्रेम, रंग-बिरंगे झंडों और उमंग से सराबोर था। यह आयोजन शिक्षकों, विद्यार्थियों और अतिथियों की सहभागिता से अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसे श्री के.के. यादव जी (उप निरीक्षक) ने बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ संपन्न किया। ध्वजारोहण के पश्चात जब राष्ट्रगान की गूंज चारों ओर फैली, तब वातावरण भावनाओं और देशभक्ति से सराबोर हो गया। सरस्वती माता एवं भारत माता की पूजा अर्चना के उपरांत अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

के.के. यादव ने अपने प्रेरणादायक भाषण में कहा कि ÷स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है।÷ उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों को पहचानें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि आज जो आज़ादी हमें सहज रूप से प्राप्त है, उसके पीछे असंख्य बलिदानों की कहानी छिपी है। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया।

विशिष्ट अतिथि स्वप्निल यादव ने अपने ओजस्वी भाषण में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी युवा शक्ति है और हमें मिलकर भारत को आत्मनिर्भर एवं नवाचार प्रधान राष्ट्र बनाना है।

प्राचार्य डॉ. रेखा तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं, अपितु आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिन है। उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

श्री रितेश पटेल (प्राचार्य, केशरी फार्मेसी विभाग) ने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

श्रीमती स्वाति कश्यप ने अपने प्रेरक शब्दों से सभी को दिशा दिखाई और विद्यार्थियों को निष्ठा और परिश्रम का संदेश दिया

कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें भाषण, कविता और गीतों के माध्यम से भारत माता को समर्पण प्रकट किया गया।

शुभम देवांगन ने अपने प्रभावशाली भाषण में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाया और युवाओं को कर्तव्यनिष्ठा की ओर प्रेरित किया।

शिवरात्रि कंवर ने अपनी मधुर स्वर-लहरियों में बंधा देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर कर दिया।

सत्या राठौर ने हृदयस्पर्शी देशभक्ति कविता के माध्यम से भारत माता के प्रति प्रेम को स्वर दिया।सपना गुप्ता ने अपने शब्दों से विद्यार्थियों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागृत की।

विकासनी ने भी प्रेरणादायक कविता के माध्यम से सबके मन को छू लिया।

नितेश तिवारी तथा पंकज ने अपने जोशीले भाषण से आयोजन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति केवट और ओमप्रकाश चंद्रा ने अत्यंत सजीवता एवं प्रभावशाली शैली में किया, जिससे संपूर्ण कार्यक्रम में उत्साह और अनुशासन का अद्भुत समन्वय बना रहा।

इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में श्री जितेंद्र तिवारी , श्रीमती आशा तिवारी एवं सुश्री राखी पाण्डेय का विशेष सहयोग रहा, जिनके मार्गदर्शन और समर्पण से कार्यक्रम की गुणवत्ता और उत्साह दोनों चरम पर पहुँचे

कार्यक्रम का समापन श्रीमती स्वाति कश्यप द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आयोजकों का धन्यवाद किया तथा देश के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखने का संदेश देते हुए कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा की।

नगर सेना भर्ती हेतु परीक्षा परिणाम जारी

जांजगीर-चांपा 1715 महिला नगर सैनिकों की छात्रावास ड्यूटी हेतु तथा 500 महिला एवं पुरुष नगर सैनिक जनरल ड्यूटी हेतु भर्ती कार्यवाही की गई है। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जिसका परिणाम 08 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। उक्त भर्ती परिणाम विभागीय वेबसाइट httpsÑ//www.cghgcd.gov.in एवं httpsÑ//firenoc.cg.gov.in में अपलोड किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 01 से 10 सितम्बर 2025 तक जिला मुख्यालय में अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज तथा 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 03 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ उपस्थिति होना सुनिश्चित करेंगे। नगर सेना भर्ती परीक्षा परिणाम हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन कर सकते है।

लायंस क्लब ने नवजात शिशुओं को किया सुरक्षा किट का वितरण

लोकशक्ति

नवजात शिशुओं को सुरक्षा किट वितरण करते लायन सदस्यगण

म्यूजिक रूम के शुभारंभ पर मौजूद लायन सदस्यगण

चांपा। स्थानीय समाजसेवी संस्था लायंस क्लब चांपा द्वारा क्लब के संचालक मंडल एवं सामान्य सभा की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार रविवार 17 अगस्त को श्रीमती हेमिनबाई रामनारायण राठौर मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती 19 नवजात शिशुओं की माताओं को बच्चों की सुरक्षा के लिए हिमालिया कंपनी की ओर से प्रदत्त सुरक्षा किट का वितरण किया गया। इस मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन संतोष कुमार सोनी ने कहा कि क्लब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कार्य संपादित करता है इसके तहत समय समय पर जरूरतमंद लोगों की आवश्यकतानुरूप उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास क्लब द्वारा निरंतर किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित लायन डॉ. के. पी. राठौर ने कहा कि नवजात शिशुओं को प्रारंभिक दिनों में अधिक सुरक्षित देखभाल की जरूरत होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें सुरक्षा किट का वितरण किया जा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉ. अतुल राठौर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लायन सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर लायंस क्लब शिक्षण समिति के चेयरमेन लायन रामप्रपन्न देवांगन सहित लायन डॉ. योगेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष लायन वासुदेव देवांगन विशेष रूप से उपस्थित थे। यह जानकारी लायंस क्लब के सचिव लायन राजेश अग्रवाल ने दी।

लायंस स्कूल में हुआ संगीत कक्ष का शुभारंभ

चांपा। स्थानीय समाजसेवी संस्था लायंस क्लब चांपा द्वारा संचालित लायंस इंग्लिश हायर सेकेण्ड्री स्कूल में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर स्कूल के उद्यान के पास नवनिर्मित भवन में संगीत कक्ष का शुभारंभ लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन संतोष कुमार सोनी तथा लायंस क्लब शिक्षण समिति के चेयरमेन लायन रामप्रपन्न देवांगन ने किया।

इस मौके पर लायन संतोष कुमार सोनी ने कहा कि लायंस स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संगीत प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से यहां संगीत कक्ष का शुभारंभ किया जा रहा है। लायंस वलय शिक्षण समिति के चेयरमेन लायन रामप्रपन्न देवांगन ने कहा कि स्कूल में संगीत कक्ष के शुभारंभ से विद्यार्थियों की संगीत प्रतिभा निखरकर सामने आयेगी। प्राचार्य श्रीमती अजिता वी. के. ने कहा कि नवनिर्मित संगीत कक्ष में सभी वाद्य यंत्र उपलब्ध कराये गये है। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में छिपी संगीत प्रतिभा को मंच प्रदान होगा। इस अवसर पर लायन वासुदेव देवांगन, लायन डॉ. के. पी. राठौर, लायन डॉ. योगेन्द्र शर्मा, लायन डॉ. संतोष अग्रवाल, लायन नारायण सोनी, लायन विनोद कुमार अग्रवाल, लायन बैजनाथ देवांगन, लायन सीए सुरेश अग्रवाल, लायन नंदकुमार देवांगन सहित श्रीमती संजना सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे।

बीस लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ाया

जांजगीर चांपा

जांजगीर चांपा / बीस लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को पामगढ़ पुलिस ने पकड़ा है । ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें मुखबिर सूचना रेड कार्यवाही कर आरोपी रामनारायण यादव निवासी सेमरिया थाना पामगढ़ के कब्जे 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रूपए एवं परिवहन में पुराना मोटर सायकल जिसका को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 372/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि संतोष बंजारे, आर. राघवेंद्र घृतलहरे, महेन्द राज, लखेश्वर पाटले, म.आर. सविता पटेल का योगदान रहा।

शराब भट्टी में घुसकर रुपए पैसे एवं शराब की मांग

आरोपी आशीष उर्फअस्सु ठाकुर को अकलतरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

लोकशक्ति

जांजगीर चांपा / शराब भठ्ठी में घुसकर रुपए पैसे की मांग व मारपीट के आरोपी को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है । प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 अगस्त 2025 को आरोपी आशीष उर्फ अस्सु ठाकुर निवासी कोटमीसोनार के द्वारा शाम लगभग 5 बजे अकलतरा शराब भट्टी के पास शराब के नशे में आया और शराब भट्टी में घुसकर शराब और पैसे मांगने लगा ।शराब भट्टी के सेल्समेन एवं मैनेजर के द्वारा शराब एवं पैसे नहीं देने से भट्टी के काउंटर के अंदर घुस गया व उनके साथ गाली -गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा। प्रार्थी मुकेश कुमार नायक कि रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में आरोपी आशीष ठाकुर को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

आरोपी आशीष उर्फ अस्सु ठाकुर के विरुद्ध जुआ एक्ट, एससी एसटी एक्ट समेत कई प्रकरण दर्ज हैं । उसके विरुद्ध पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है परंतु कोई सुधार नहीं हो रहा है जिस कारण से आरोपी का गुंडा बदमाश फाइल तैयार कर की गई है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा एवं थाना अकलतरा स्टाफका सराहनीय योगदान रहा।

लापता किशोर की तलाश जारी......

जांजगीर नैला। शहर के प्रेम कश्यप पिता दिलहरण कश्यप उर्फ ननकी दाऊ निवासी वार्ड 4 नैला जिला-जांजगीर-चाम्पा पुरानी बस्ती नैला का है। जो 13 अगस्त से लापता है। लापता प्रेम कश्यप जिसका उम्र 15 वर्ष है जो मांनसिक दिव्यांग है वह बुधवार 13 अगस्त शाम

6 बजे से नैला बुधवारी बाजार से कहीं चला गया है और उनकी खोज विभिन्न क्षेत्रों में तालाश कर किया जा रहा है । उसकी गुम होने की रिपोर्ट नैला चौकी (थाना जांजगीर) में भी कराया जा चुका है। चूंकि वह बालक मानसिक दिव्यांग है बोल-चाल ठीक से नहीं पाता है। जिसके कारण वह कही आस-पास में नहीं मिल रहा है। वह अपने घर का भी पता नहीं बंता सकता। विगत 6 दिनों से पुत्र प्रेम कश्यप की तालाश की जा रही है किंतु कहीं भी पता नहीं चल रहा है अपितु आप जिस किसी भी लोगों को पता चलें निम्न पते पर ,दिलहरण कश्यप उर्फननकीदाउ वार्ड नं.04 नैला बैगापारा पुरानी बस्ती नैला मो.नं.-9630756650 में खबर करने की कृपा करेंगे। खबर देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा।

कांग्रेस जनों ने मनाया स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती

जांजगीर चांपा / आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 81 वां जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश पैगवार के संयोजन में 20 अगस्त को जांजगीर शहीद स्मारक में प्रार्थना सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर, धूप दीप प्रज्वलित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारत के नवनिर्माण और विकास का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने में हमें मिलजुल कर पूरा शक्ति के साथ जुटने के लिए उपस्थित कांग्रेस जनों ने संकल्पित हुए

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप, जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश पैगवार, प्रदेश कांग्रेस सचिव हर प्रसाद साहू, डॉ परस शर्मा, , रफीक सिद्दीकी, विवेक सिसोदिया, भगवान दास गढ़वाल, शिशिर द्विवेदी, संतोष पप्पू शर्मा, शत्रुघ्न दास महंत, श्रीमती सीमा राजू शर्मा,श्रवण सिंह,संतोष बबई गढ़वाल , रामविलास राठौर,अनिल चौरसिया, मुस्कान परवीन, चंद्र कुमार ओग्रे, दीपेंद्र कहरा, विजय गढेवाल,अतिक कुरैशी, कमलेश ताम्रकार, नरसिम्हा यादव, आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए

धरदेई व मेउभांठा में बनेगा महतारी सदन,

विधायक शेषराज हरवंश की अनुशंसा पर मिली स्वीकृति

30 - 30 लाख की लागत से होगा निर्माण

जांजगीर-चांपा। पामगढ़ विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश की अनुशंसा पर उनके विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत ग्राम धरदेई व मेउभांठा में महतारी सदन का निर्माण होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 13 अगस्त 2025 को आदेश प्रसारित कर 30 - 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले दिनों विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर सीएलएफ की संलग्न सूची के आधार पर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धरदेई और ग्राम पंचायत मेउभांठा में महतारी सदन निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करने कहा था। जिस पर शासन द्वारा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत

धरदेई और ग्राम पंचायत मेउभांठा में महतारी सदन निर्माण के लिए 30-30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। गांव में महतारी सदन बन जाने से महिलाओं को बैठक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए एक सर्वसुविधा भवन मिल जाएगा।

''छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव'' अंतर्गत विविध कार्यक्रम का किया गया आयोजन

जांजगीर-चांपा

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में रजत जयंती वर्ष 2025 के अवसर पर ''छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव'' अंतर्गत जिले की सभी परियोजनाओं में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में बलौदा में व्यंजन प्रतियोगिता के माध्यम से स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। बाल मेले में बच्चों द्वारा बनाए गए खिलौनों की प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई। पामगढ़ परियोजना में बालिका सुरक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 142 महिलाएं और 82 किशोरी बालिकाओं का एच.बी./एनीमिया एवं पोषण जांच किया गया। नवागढ़ में साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र, प्रश्नोत्तरी एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध सेवाओं - परामर्श, चिकित्सकीय सहायता, विधिक सहायता, पुलिस सहयोग, अस्थायी आश्रय, महिला हेल्पलाइन 181 एवं डायल 112 के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बाल संरक्षण इकाई की कार्यप्रणाली एवं विभागीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर का वितरण किया गया।

भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चाम्पा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) रायपुर अंतर्गत भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चाम्पा एवं बरगढ़ (उड़ीसा) में जुलाई 2025 से प्रारंभ होने वाले डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में 30 सीट एवं लेटरल एण्ट्री के आधार पर सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 26 सीट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

प्राचार्य भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना एवं आयु सीमा 01 जुलाई 2025 को 15 से 23 वर्ष एवं एसटी, एससी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 17 से 25 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु गणित, भौतिकी एवं रसायन विषय सहित 12वीं की परीक्षा के साथ वस्त्र प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त विषय सहित 10वीं परीक्षा के साथ 02 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त 12वीं परीक्षा के साथ 02 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिसकी आयु सीमा 01 जुलाई 2025 को 17 से 25 वर्ष के बीच एवं एसटी, एससी के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 17 से 27 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आवेदन पत्र संस्थान के वेबसाईट www.iihtchampa.org.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। स्वप्रमाणित आवेदन पत्र पोस्ट द्वारा iihtchampacg@gmail.com में ईमेल द्वारा, स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 29 अगस्त 2025 को सायं 5.00 बजे तक प्राचार्य, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, मड़वा प्लांट रोड, लछनपुर चौक, चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) 495669 में जमा किया जा सकता है।

खास खबर

आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती हेतु दावा आपत्ति 1 सितम्बर तक

बिलासपुर । एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी अंतर्गत ग्राम पंचायत केकराड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका पद के लिए प्राप्त आवेदनों के जांच उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार कर जारी कर दिये गये। जिसके विरूद्ध दावा आपत्ति 22 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने भारतीय सद्भावना समाज पार्टी को दिया नोटिस

संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग ने लम्बे समय से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने पर भारतीय सद्भावना समाज पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव को 29 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे जवाब देने के लिए शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में बुलाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर के खान मंजिल, खपरगंज के पते से भारतीय सद्भावना समाज पार्टी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत था। लेकिन उनका वर्तमान पता ज्ञात नहीं है। इस पार्टी ने वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों में लोक सभा, विधानसभा अथवा उप चुनाव में किसी भी चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इससे लगता है कि पार्टी ने राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत दलों की सूची से राजनीतिक पार्टी भारतीय सद्भावना समाज पार्टी को हटाने का प्रस्ताव किया है। सुनवाई के बाद आयोग द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

महिलाओं के लिए निःशुल्क प्लेसमेंट कैम्प 20 को

निजी कंपनी करेगी 500 पदों पर भर्ती

बिलासपुर । जिले की महिला अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 अगस्त को सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा एवं शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर में निःशुल्क प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इन कैम्पों में एटीसी टायर्स प्राईवेट लिमिटेड दहेज, जिला भरूच, गुजरात द्वारा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 500 मशीन ऑपरेटर के पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। इच्छुक महिला अभ्यर्थी जो 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक (किसी भी विषय में) उत्तीर्ण हैं, वे कैम्प में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी रोजगार कार्यालय की वेबसाईट www.erojgar.cg.nic.in, रोजगार एप एवं संबंधित महाविद्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने एक-एक योजनाओं की समीक्षा कर संतृप्ति लेवल हासिल करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। प्रमुख रूप से बैठक में छत्तीसगढ़ निर्माण की रजत जयंती समारोह, सड़क सुरक्षा, गौधाम योजना, शोरगुल रोकने आदि विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्धारित समय 10 बजे कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। अधिकारियों के समय पर पहुंचने पर मातहत कर्मचारियों पर भी दबाव रहेगा। समय पर उपस्थिति नहीं देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं पीएम पोर्टल में दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी

ली। कलेक्टर ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। फिलहाल केवल 39 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 300 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया। उन सभी किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा। बैठक में सड़क पर से हटाये गये बैल जोड़ी के बैगा किसानों में वितरण की जानकारी भी ली। बताया गया कि अब तक 67 जोड़ी बैल का वितरण किया जा चुका है। जबकि किसानों से 1087 जोड़ी बैल की मांग आई है। मोपका एवं रहंगी गोठान में रखे बैलों का स्वास्थ्य परीक्षण करके इन्हें भी बांटने के निर्देश पशुधन विकास विभाग को दिए गये।

कलेक्टर ने शहर के प्रवेश द्वार के रूप में चिन्हित पेण्ड्री चौक के सौन्दर्यीकरण करने के निर्देश दिए। चौक के आस-पास ठेले अथवा वाहन खड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए इसकी बैरिकेडिंग किया जाये। दरीघाट से पेण्ड्री तक एनएचएआई में बंद पड़े लाईट को सुधारने कहा है। बैठक में बताया गया कि कानफोड़ू आवाज वाले 8 डीजे संचालकों पर पिछले सप्ताह कार्रवाई की गई। उनका डीजे सेट जब्त कर वाहन लाईसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने अटल मॉनीटरिंग पोर्टल की भी समीक्षा की। पीएम जनमन में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए यह पोर्टल शुरू की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सड़कों से पशुओं को हटाने और उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना प्रारंभ की है। बरसात में खराब हुए सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य-योजना तैयार रखने को कहा ताकि पानी के कम होने पर तत्काल सुधार कार्य शुरू किया जा सके। धान खरीदी की तैयारी की भी कलेक्टर ने समीक्षा की।

नाव पलटने से युवक की मृत्यु

कोरबा जिले के मोरगा चैकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर में मछली पकड़ने नाव लेकर नदी में गए 42 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार युवक नदी के बीचों-बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नाव में पानी भरने लगा और नाव पलट गई। युवक तैरकर बाहर नहीं निकल पाया और डूब गया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पिछले दो दिनों से उसकी तलाश जारी थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार नदी से शव बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला मोरगा चैकी क्षेत्र अंतर्गत का है। जहां ग्राम मदनपुर में निवास करने वाले रामकुमार मरकाम उम्र (42 वर्ष) 15 अगस्त को मोनासी नदी में मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर गया हुआ था। लगभग दोपहर लगभग 12. 30 बजे नदी के बीचो-बीच पहुंचा हुआ था और मछली पकड़ने में लगा हुआ था कि इसी दौरान धीरे-धीरे कर उसके नाव में पानी भरता चला गया और उसे पता नहीं चला। जब नाव का बैलेंस बिगड़ा, तब उसे पता चला कि नाव में पानी भर चुका है और इस बीच नाव पलट गई और वह नदी में वह डूब गया। आसपास के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी गई। जिसके बाद उसके परिजनों ने इसकी सूचना मोरगा चैकी पुलिस को दी। मोरगा पुलिस की टीम पिछले दो दिनों से गोताखोरों की मदद से मोनासी नदी में रामकुमार मरकाम की खोजबीन कर रही थी।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

बिलासपुर

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों की निजी और सामुदायिक समस्याएं इत्मीनान से सुनी और अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनदर्शन में आए किसानों से चर्चा कर खेती-किसानी के ताजा हालात की जानकारी ली। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।

साप्ताहिक जनदर्शन में जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम साल्हेकापा के सरपंच एवं ग्रामीणों ने नहर की साफ सफाई एवं मरम्मत किये जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि नहर के मरम्मत एवं साफ-सफाई की आवश्यकता है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम पंचायत लोखण्डी के ग्रामीणों ने

कोलवासरी के ट्रकों एवं हाईवा द्वारा जर्जर हो चुके सड़क की मरम्मत के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में बड़े तादाद पर कोलवासरी का संचालन होने के कारण सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग पर छोटे बड़े कई घर, स्कूल, आंगनबाड़ी का संचालन होता है जिससे किसी गंभीर दुर्घटना होने का भय बना रहता है। कलेक्टर ने खनिज विभाग को आवेदन सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत ऊनी के सरपंच ने ग्राम में लीलागर नदी में एनीकेट निर्माण कराने जाने के संबंध में आवेदन दिया। सरपंच ने बताया कि गर्मियों के दिनों में नदी सूखने के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे निस्तारी सहित अन्य कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनीकेट निर्माण होने से निस्तारी सहित जल स्तर में वृद्धि भी होगी और पानी का भी संरक्षण होगा। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। ग्राम पंचायत लोखण्डी के सरपंच, पंचों सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण होने के कारण पानी की पाईप लाईन टूट गयी है, जिसके कारण पेयजल का आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। कलेक्टर ने इस मामले को पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तुरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाराघाट के ग्रामीणों ने राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड प्लांट द्वारा लीलागर नदी में विषैला पानी छोड़ने व चिमनी से निकलने वाले धुएं से फैल रही बीमारियों के रोकथाम एवं इस संबंध में जांच करने की मांग की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उद्योग विभाग को जांच करने के निर्देश दिए है।

एसएजीईएस, एनसीडीसी की टीम ने प्राप्त किया प्रथम स्थान

जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का सफल आयोजन

कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी टी.पी. उपाध्याय के मार्गदर्शन एवं नोडल अधिकारी बी.पी. कश्यप के कुशल संचालन में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय (एसएजीईएस), जमनीपाली में संपन्न हुआ।

इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतियोगिता के अवसर पर कार्यक्रम संयोजक पी.डी. मनिकपुरी एवं एस.एस. खान सहित शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में जी.पी. बंजारें, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लफा एवं श्रीमती मंजू तिवारी, प्राचार्य एसएजीईएस दादरखुर्द, ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में एसएजीईएस, एनसीडीसी की टीम ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

यह टीम अब आगामी सितंबर माह में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी।

नव पदोन्नत 845 प्राचार्यों के पदांकन के लिए 20 से 23 तक रायपुर में ओपन काउंसिलिंग

कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन हेतु ओपन काउंसिलिंग का आयोजन 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। इस काउंसिलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसिलिंग का समय प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से निर्धारित है। प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसिलिंग की तिथि एवं समय की जानकारी पदोन्नत प्राचार्यों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा। व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति आदेश के लिए काउंसिलिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारण (प्रथम चार का क्रम निर्धारण) व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.), प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची (व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 2:1:1 में तैयार की गई है। उपरोक्त अनुपात भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसार व्याख्याता 65 प्रतिशत (व्याख्याता 70 प्रतिशत तथा व्याख्याता एल.बी. का कोटा 30 प्रतिशत है) जबकि प्रधान पाठक (मा.शाला) 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित है। सर्वप्रथम एक वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

मनरेगा की डबरी से खेतों में आई हरियाली, किसानों के चेहरों पर मुस्कान

किसान आशीष को मिला संबल, बढ़ा जल स्तर और रोजगार के अवसर

बिलासपुर (लोकशक्ति)।

मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डबरी निर्माण कार्य से किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा जल का स्थायी साधन मिल रहा है। इस पहल से खेती-किसानी में सुधार हुआ है और किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। मनरेगा के तहत बनी डबरी किसानों के जीवन में संजीवनी साबित हो रही है। बरसात का पानी अब व्यर्थ बहने की बजाय खेतों में फसलों को सींच रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की मेहनत रंग ला रही है, बल्कि खुशहाली की नई राह

भी खुल रही है। जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत एमरसाही के किसान आशीष को भी मनरेगा योजना के तहत डबरी निर्माण का लाभ मिला है।

ग्राम पंचायत एमरसाही के ग्राम सभा में ग्रामीण किसान आशीष के लिए मनरेगा योजना से डबरी निर्माण कार्य करने के लिए सर्व सम्मति से ग्राम सभा में प्रस्ताव प्रास किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के पश्चात उनके निजी भूमि में डबरी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। डबरी निर्माण कार्य महज़ दो माह में पूरा किया गया, जिसमें 955 मानव दिवस सृजित हुए। इससे गाँव के कई लोगों को काम मिला। लगभग 1 लाख 72 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए इस कार्य से न केवल जल संचयन की व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि रोजगार और कृषि विकास के नए अवसर भी बने हैं। डबरी से खेतों की सिंचाई आसान हो गई है और जल स्तर में भी सुधार हुआ है। किसान आशीष का कहना है कि इस कार्य से उनकी फसल को बेहतर उत्पादन मिल रहा है और पशुपालन की व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है।

सिरपुर में राज्य स्तरीय एडवेंचर हाईक व्यक्तित्व विकास एवं प्राकृतिक अध्ययन शिविर का आयोजन

राज्य भर के 100 स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर ने लिया भाग

लोकशक्ति

बिलासपुर (संवाददाता)। भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल सांसद एवं राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव के नेतृत्व व निर्देशन एवं राज्य सचिव कैलाश सोनी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय के तत्वाधान में स्काउटिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरुप छत्तीसगढ़ राज्य संघ नित नए-नए आयाम को छू रहा है। इसी कड़ी में ग्राम जलकी, सिरपुर महासमुंद में 11 से 14 अगस्त तक चार दिवसीय राज्य स्तरीय एडवेंचर हाईक व्यक्तित्व विकास एवं प्राकृतिक अध्ययन शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 2 राज्य प्रभारियों सहित छत्तीसगढ़ राज्य भर के विभिन्न जिलों के 100 स्काउट-गाइड, रोवर्स-रेंजर्स ने भाग लिया। जिसमें उन्होंने ग्राम जलकी के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में न केवल विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया बल्कि विभिन्न रोमांचक साहसिक कार्यो जैसे जिप लाइन, जॉइंट स्विंग,

रोपब्रिज, मंकी ब्रिज, टायर वॉल क्लाइंबिंग, रिवर रॉफ्टिंग, तीरंदाजी, गन शूटिंग आदि उत्साह पूर्वक एक्टिविटी में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का भी विकास किया। हाईक में इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ (दक्षिण कौशल) की प्राचीन राजधानी सिरपुर (श्रीपुर) के पुरातात्विक एवं इतिहास स्थलों जैसे लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर सुरंग टीला सहित विभिन्न प्राचीन स्थलों का अवलोकन भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिला संघ बिलासपुर के जिला मुख्य आयुक्त चन्द्र प्रकाश बाजपेयी एवं पदेन जिला आयुक्त स्काउट/जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार यादव एवं राज्य संगठन आयुक्त स्काउट विजय यादव ने सराहना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही जिला संघ बिलासपुर के सभी पदाधिकारियों एवं सक्रिय स्काउटर एवं गाइडर में हर्ष व्याप्त है। जिला संघ बिलासपुर की 15 रोवर्स, 15 रेंजर्स, जिला प्रभारी के रूप में लक्ष्मण कुमार रजक, सुश्री निशा साहू ने दल का प्रतिनिधित्व किया।

मेमर्स जीनेक्श इंफ्रा इस्ट्रक्चर कंपनी के पदाधिकारी द्वारा लापरवाहीपूर्वक एवं बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कराने से कार्य के दौरान मृत्यु के मामले में अपराध दर्ज

कोरबा दर्री पुलिस ने मेमर्स जीनेक्श इंफ्रा इस्ट्रक्चर कंपनी के पदाधिकारी एवं जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा लापरवाहीपूर्वक (उपेक्षापूर्ण) एवं बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कराने से कार्य के दौरान मृत्यु के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। थाना दर्री में 15 अगस्त 2025 को थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर से शून्य पर कायम मर्ग क्रमांक 00/84/25 धारा 194 बीएनएसएस मृतक सुरेन्द्र कुमार साहू की मर्ग डायरी नंबरी कराने हेतु लाया गया। सूचक सूरज नगारची पिता यशवंत नगारची 27 वर्ष पता कालडा बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर कलर मॉल के पास पचपेडीनाका रायपुर की सूचना पर मर्ग कायम किया गया। सूरज नगारची की ओर से दर्री पुलिस ने मेमर्स जीनेक्श इंफ्रा इस्ट्रक्चर कंपनी के पदाधिकारी एवं जिम्मेदार व्यक्ति पर उपेक्षापूर्ण कार्य कराने के अपराध में धारा 106-बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। दुर्घटना एनटीपीसी पावर प्लांट दर्री में 07 अगस्त 2025 को सुबह 10.30 हुई थी। इलेक्ट्रिक का काम करते समय अचानक से (6000 व्ही) करंट के संपर्क में आ जाने के कारण ठेका कर्मी सुरेंद्र साहू पिता रामकुमार साहू 25 वर्ष, निवासी अयोध्यापुरी दर्री और सीएसईबी इंजीनियर आकाश कुजूर गंभीर रूप से झुलस गए थे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

रायपुर। पंडित गिरजाशंकर मिश्रा शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, रायपुरा में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बीईओ एवं प्राचार्यों ने भाग लिया।बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों के दायित्व को लेकर गहन चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट कहा कि विद्यालयों के समग्र सुधार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राचार्यों पर है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने निर्देशित करते हुए कहा कि :- बच्चों की अनुपस्थिति पर नियंत्रण ङ्क अनुपस्थित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्राचार्य अभिभावकों से संवाद करें, ग्राम पंचायत व सरपंच की मदद लें तथा घर-घर जाकर प्रेरित करें। शिक्षकों की जवाबदेही ङ्क यदि कोई शिक्षक पढ़ाने में अक्षम पाया जाता है तो उनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। ऐसे शिक्षकों को ऑनलाइन मॉड्यूल व वीडियो लेक्चर से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। सिलेबस की समयबद्ध समीक्षा ङ्क प्रत्येक माह सिलेबस की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। निर्धारित समय पर सिलेबस पूरा न होने पर संबंधित शिक्षक व प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। स्मार्ट क्लास का उपयोग ङ्क जिन विद्यालयों में शिक्षक की कमी है वहाँ स्मार्ट क्लास, टीवी और वेब ड्राइव का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा 7 विशेष परियोजनाएँ : प्रोजेक्ट दधीच :- अंगदान व पुस्तक दान की प्रेरणा दी। प्रोजेक्ट छांव : स्वास्थ्य एवं वेलनेस संबंधी पहल 7 शिक्षक-निर्मित वीडियो :- विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं को समझाने हेतु छोटे वीडियो तैयार कर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बैठक में हरियर पाठशाला, प्रोजेक्ट धड़कन सहित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्देश दिया कि सभी विषयों एवं स्कूलों की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक नियमित रूप से की जाए।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती, डीएमसी श्री केएस पटले, एपीसी श्री अरुण शर्मा समस्त बीईओ एवं प्राचार्य उपस्थित रहे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने किया निरीक्षण

रायपुर । जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया जा रहा है है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुँचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सर्वे को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने ग्राम सेरीखेड़ी और मंदिर हसौद तहसील में खेतों का निरीक्षण किया और सर्वे की प्रगति जानी। इसके अलावा, कलेक्टर ने ग्राम लखौली (तहसील आरंग) में भी डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ड्रोन तकनीक से नैनो डीएपी छिड़काव की प्रक्रिया का निरीक्षण कर इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, आरंग एसडीएम सुश्री अभिलाषा पैकरा, एसडीएम रायपुर श्री नंदकुमार चौबे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ग्राम कनकी (खरोरा तहसील) तथा दोंदेखुर्द, धरसींवा में भी पहुँचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुश्री नम्रता जैन आईएएस ने ग्राम छांटा, गोबरा नवापारा में डिजिटल क्रॉप सर्वे का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों की स्थिति जानने एवं सटीक आंकड़े एकत्र करने में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें।

प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के विषय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता से सरकार के कार्यों को बल मिलेगा। बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मध्य एमओयू सम्पादित किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में शिक्षा,स्वास्थ्य, क्रेच(शिशुगृह),आजीविका विकास सहित अन्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों के विषय में पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग बेहार ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा विगत 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 9 जिलों में फाउंडेशन द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में फाउंडेशन की भविष्य की कार्ययोजना से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अम्बिकापुर में 200-300 बिस्तर का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और धर्मजयगढ़ में 100 बिस्तर का सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की योजना है। इन अस्पतालों में अस्सी प्रतिशत प्रतिशत मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय को फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में शासकीय विद्यालयों से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई करने वाली 20 हजार बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके तहत बालिकाओं की ट्यूशन फीस के साथ अन्य खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने स्कॉलरशिप देने की योजना की सराहना की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय को फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य संस्थागत रूप से किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 6 महीने से 3 साल तक के छोटे बच्चों के लिए राज्य में 400 क्रश (शिशुगृह) संचालित हैं। सभी क्रश में बच्चों को दिन में 3 बार भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। फाउंडेशन की योजना प्रदेश में क्रेच की संख्या को बढ़ाकर 2500 से 3000 क्रेच तक करने की है।

नहीं चलेगी 'पेशी पर पेशी': मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को दिए स्पष्ट निर्देश

लंबित राजस्व मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त, राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली सभी जिलों के कलेक्टर्स की समीक्षा बैठक

रजत महोत्सव की तैयारियों और विकास योजनाओं की प्रगति की गहराई से समीक्षा

राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी, राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी नजर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। राज्य में बढ़ते लंबित राजस्व प्रकरणों पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाते हुए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब ÷पेशी पर पेशी÷ का दौर खत्म हो– सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जाए।मुख्यमंत्री श्री साय ने जिलेवार समीक्षा करते हुए नामांतरण, अविवादित व विवादित बंटवारे, अभिलेख दुरूस्ती, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन, सीमांकन, और डायवर्सन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से जनता को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनका समय और श्रम भी व्यर्थ जाता है। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा भी कम होता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेशियों में कमी लाएं और प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज किया जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग आसान हो सके। साथ ही रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और त्रुटि सुधार के मामलों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। तहसील स्तर पर पटवारियों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर खास जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना की तीव्र और निर्बाध गति के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया जरूरी है।उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि भू-अर्जन और मुआवजा वितरण के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें।

बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और मुआवजा वितरण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार अब राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एक जिम्मेदार शासन प्रणाली का निर्माण तभी संभव है जब जनता के साथ न्याय समय पर हो। इसलिए प्रत्येक अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रकरणों का निपटारा देरी के बिना, न्यायसंगत ढंग से हो।मुख्यमंत्री ने किसान पंजीयन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही सभी पात्र किसानों का पंजीयन पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वे को गंभीरता से लेने और समय पर पूर्ण करने को कहा। छत्तीसगढ़ के निर्माण की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए 15 अगस्त से रजत महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो 25 सप्ताह तक चलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आयोजन कर रजत महोत्सव को जनभागीदारी का उत्सव बनाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में 'सेवा पखवाड़ा' मनाया जाएगा जो छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का हिस्सा होगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप, राजस्व कैम्प जैसे जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अलग-अलग क्षेत्र से तीन दोपहिया वाहन पार

रायपुर । राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोर ने तीन दोपहिया वाहन पार कर दिया। तीनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में डब्ल्यूआरएस कालोनी निवासी ओमप्रकाश रात्रे 52 वर्ष ने खमतराई थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एलयू 2241 को खमतराई मछली बाजार के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है।

वहीं दूसरे मामले में छीर्रापारा बिलाईगढ़ निवासी प्रार्थिया सुनीति साहू 26 वर्ष ने पुरानी बस्ती थाना में शिकायत किया कि वह अपनी स्कूटी क्रमांक सीजी 22 यू 2808 को भाठागांव ओव्हरब्रीज के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं तीसरे मामले में शिव विहार कालोनी डीडीनगर निवासी प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू 57 वर्ष ने सिविल लाइन थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 सीटी 0173 को कलेक्ट्रेट के टाउन हाल के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 5 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है।

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पितः श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल में स्पाइन चिकित्सा हेतु अत्याधुनिक ओ-एआरएम विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मात्र 20 माह के इस अल्प समय में राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया है। इसका परिणाम है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार उच्च स्तरीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ एवं अंबिकापुर में 100-100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों की स्थापना हेतु देश की प्रतिष्ठित संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। आम जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पहले

ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए किसानों को खेत बेचने और कर्ज लेने की स्थिति आ जाती थी, परंतु आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बड़े से बड़े अस्पताल से लेकर छोटे अस्पताल तक में निःशुल्क इलाज संभव हुआ है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वेलनेस सेंटरों के संचालन और जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों को अधिक खर्च न उठाना पड़े।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अत्याधुनिक ओ-एआरएम विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन की स्थापना के लिए श्री नारायणा हॉस्पिटल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इसका लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मरीजों को ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से उपचार हेतु आने वाले मरीजों को भी मिलेगा।इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और श्री नारायणा हॉस्पिटल में शुभारंभ हुई इस अत्याधुनिक मशीन के लिए पूरी टीम को बधाई दी।कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री किरण देव, श्री मोती लाल साहू, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. सुब्बीर मुखर्जी, श्री नारायणा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. सुनील खेमका सहित हॉस्पिटल समूह के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

न्यायालय में गवाही देने से रोकने के लिए धमकी देने वाले हिस्ट्रीशीटर समेत 6 आरोपी

रायपुर । रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में न्यायालय में गवाही देने से रोकने के लिए प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने वाले हिस्ट्रीशीटर सहित छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला तिल्दा नेवरा निवासी प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट पर आधारित है, जो थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 109/2021 धारा 376, 120बी, 450, 506, 307 भादवि. के गंभीर मामले में साक्षी है। यह प्रकरण आरोपी बालकृष्ण जांगड़े द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर हत्या की नीयत से जानलेवा हमला करने से जुड़ा है। प्रार्थी प्रमोद वर्मा को दिनांक 07 अगस्त 2025 को रायपुर न्यायालय में गवाही के लिए नोटिस प्राप्त हुआ था। गवाही देने से पहले ही उसे और उसके परिवार को आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा बार-बार धमकियां दी जा रही थीं। जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा, सूरज वर्मा, रवि उर्फ गप्पू वर्मा, रजत वर्मा, अजय राहूजा एवं दीपक उर्फ बबलू वर्मा ने मोबाइल फोन के जरिए और घर जाकर धमकी दी कि यदि वह गवाही देगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। साथ ही, आरोपी पक्ष से समझौता करने का दबाव भी बनाया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी और थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमुख नाम जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा का है, जो तिल्दा नेवरा थाने का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है और जिस पर पहले से दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा 33 वर्ष निवासी सासाहोली, सूरज वर्मा 26 वर्ष निवासी श्याम नगर, रवि उर्फ गप्पू वर्मा 31 वर्ष निवासी तुलसी नेवरा, रजत वर्मा 24 वर्ष निवासी छतौद, अजय राहूजा 23 वर्ष निवासी सासाहोली व दीपक उर्फ बबलू वर्मा 41 वर्ष निवासी जोता इन सभी के विरुद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 358/25 धारा 232(1), 190 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में देशभर में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति : मुख्यमंत्री

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति : मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा, एटीएम और डिपॉजिट मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन के कर्मचारियों, नवा रायपुर के आसपास निवासरत नागरिकों तथा बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों को शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले योजनाओं की राशि का वितरण नगद रूप में किया जाता था, जिससे लीकेज की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार

और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हितग्राहियों तक राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापना के साथ-साथ बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा है। सरगुजा और बस्तर अंचल के दूरस्थ गाँवों में बैंक शाखाओं की स्थापना से सरकार का ÷अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने÷ का संकल्प साकार हो रहा है।

वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश के बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उन्होंने बैंकों से भी इस दिशा में अपनी सक्रिय व प्रभावी भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक श्री अशोक चंद्र सहित अन्य अधिकारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरगी उपकेन्द्र में 72 लाख रूपये की लागत से स्थापित किया गया 5 एम.व्ही.ए. का नया पॉवर ट्रांसफार्मर

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचलों में बिजली उपभोक्ता एवं किसानों को भरपूर वोल्टेज पर निर्बाध व गुणावत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के लिए विद्यमान पॉवर सबस्टेशनों में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर क्षमता वृद्धि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है। इस योजना के तहत राजनांदगांव ग्रामीण उपसंभाग के अन्तर्गत सुरगी 33/11 के0व्ही0 सबस्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 05 एम0व्ही0ए0 के नये पॉवर ट्रांसफॉर्मर को स्थापित कर राजनांदगांव वृत के अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर ने ऊर्जीकृत किया। ग्राम सुरगी उपकेन्द्र की क्षमता पहले 3.15 एम0व्ही0ए था, अब 05 एम0व्ही0ए0 के नये पॉवर ट्रांसफार्मर के लगाये जाने से इस उपकेन्द्र की क्षमता बढ़कर 05 ए0व्ही0ए0 हो गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि यह कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लगभग 72 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि सबस्टेशन में पहले से मौजूदा 3.15 एम0व्ही0ए0 का पॉवर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता था। खासकर धान की फसल के मौसम में लोड शेडिंग एवं लो वोल्टेज की समस्या होती थी, उक्त कार्य से लो वोल्टेज एवं लोड शेडिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। ईडी श्री सेलट ने उक्त कार्य को क्षेत्र में उपभोक्ताओं एवं किसानों के हित में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सराहनीय बताते हुए कहा कि 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र सुरगी में 05 एमव्हीए के पॉवर ट्रांसफार्मर के लग जाने से ग्राम सुरगी, कोटराभाटा, आरला, बूचीभारदा, कुम्हालोरी, बेलटिकरी, मुड़पार एवं मालपुरी के 3730 उपभोक्ता एवं किसानों को फायदा होगा। उन्होने अधीक्षण अभियंता राजनांदगांव वृत्त श्री शंकेश्वर कंवर, ईई परियोजना श्री मुकेश कुमार साहू, सहायक अभियंता श्री प्रकाश नारायण वर्मा, श्री एस0पी0 ठाकुर, श्री आर0के0 साहू, कनिष्ठ यंत्री सुश्री एकता साहू एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि पॉवर कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपभोक्ताओं एवं किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहें हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)